RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 16
अंक : 002
दि. 02.05.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मतगणना से पहले बंगाल में सख्ती: स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर भीड़ पर रोक, आरोप-प्रत्यारोप के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम

कोलकाता से लेकर राज्य के अन्य संवेदनशील इलाकों तक इन दिनों माहौल पूरी तरह सतर्कता और राजनीतिक हलचल से भरा हुआ है। मतगणना से पहले प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक मजबूत कर दिया है, वहीं राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। इस बीच सबसे बड़ा कदम यह उठाया गया है कि जिन क्षेत्रों में 'स्ट्रॉन्ग रूम' स्थित हैं, वहां किसी भी प्रकार की भीड़ जुटने पर सख्त रोक लगा दी गई है। यह फैसला उस घटना के बाद लिया गया, जिसने प्रशासन और चुनाव आयोग दोनों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल, बीती रात नेताजी इंडोर स्टेडियम स्थित मतगणना केंद्र के बाहर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हो गई। स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई थी, हालांकि पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर हालात को काबू में कर लिया। इस घटना के बाद प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कीमत पर कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। इसी के चलते शहीद खुदीराम बोस रोड, जजेज कोर्ट रोड, जादवपुर, डायमंड हार्बर रोड, लॉर्ड सिन्हा हॉल, नरेश मित्रा सरणी, बेल्टाला रोड और प्रमथेश बरुआ सरणी जैसे प्रमुख इलाकों में लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है।

राजनीतिक माहौल उस समय और गरमा गया जब कुणाल घोष और शशि पांजा ने मतगणना केंद्रों के बाहर धरना दिया और आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। कुणाल घोष ने दावा किया कि एक कमरे में, जहां कथित तौर पर डाक मतपत्र रखे गए थे, कुछ हलचल नजर आई थी, जिससे उन्हें संदेह हुआ कि कहीं न कहीं प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी हो सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सुबह के समय ऐसी कोई गतिविधि नहीं देखी गई, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है।

उनके अनुसार, पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के निर्देश पर कार्यकर्ता और उम्मीदवार लगातार उन केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं, जहां ईवीएम मशीनें 'स्ट्रॉन्ग रूम' में रखी गई हैं। ममता बनर्जी खुद भी इस मामले को लेकर काफी सक्रिय नजर आईं। उन्होंने भवानीपुर क्षेत्र में स्थित 'स्ट्रॉन्ग रूम' का दौरा किया और वहां करीब चार घंटे तक मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने मतगणना प्रक्रिया में संभावित धांधली की आशंका जताई और स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका यह कदम राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़ा करता है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने साफ शब्दों में कहा कि 'स्ट्रॉन्ग रूम' में रखी गई ईवीएम मशीनों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित है और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि इन कमरों की 24 घंटे सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है और वहां तीन स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू है, जिसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी शामिल है। उनके अनुसार, बिना ठोस सबूत के लगाए गए आरोप केवल भ्रम फैलाने का काम करते हैं और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। प्रशासनिक स्तर पर भी सतर्कता चरम पर है। कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न मतगणना केंद्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। संयुक्त पुलिस आयुक्त रूपेश कुमार ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है और हर संवेदनशील बिंदु पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक अतिरिक्त आयुक्त और एक पुलिस उपायुक्त की निगरानी में पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था संचालित की जा रही है। इसके अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा के तीन स्तर बनाए गए हैं। सबसे बाहरी घेरे में स्थानीय पुलिस तैनात है, जो आम जनता की आवाजाही पर नजर रख रही है। दूसरे घेरे में सशस्त्र पुलिस बल मौजूद है, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सकता है। तीसरे और सबसे अंदरूनी घेरे में केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात हैं, जिनकी जिम्मेदारी 'स्ट्रॉन्ग रूम' की सीधी सुरक्षा है। इसके अलावा हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिल रही है।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव केवल मतदान तक सीमित नहीं होता, बल्कि मतगणना तक उसकी संवेदनशीलता बनी रहती है। राजनीतिक दलों की ओर से लगाए जा रहे आरोप और प्रशासन की ओर से की जा रही सख्ती दोनों इस बात का संकेत हैं कि इस बार का चुनाव परिणाम बेहद महत्वपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक है। हर पक्ष अपने स्तर पर पूरी सतर्कता बरत रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।

वहीं आम जनता के बीच भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उत्सुकता और चिंता दोनों देखी जा रही है। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर परिणाम क्या होंगे, लेकिन इसके साथ ही यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। चुनाव आयोग और प्रशासन की जिम्मेदारी भी यही है कि वे इस विश्वास को बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि लोकतंत्र की यह प्रक्रिया बिना किसी विवाद के पूरी हो।

इस बीच, राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी जारी है। एक ओर तृणमूल कांग्रेस जहां लगातार निगरानी और सतर्कता की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा और अन्य दल चुनाव आयोग के भरोसे पर जोर दे रहे हैं। यह टकराव केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है, जहां हर दल अपने समर्थकों के बीच विश्वास बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।

कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले का यह माहौल बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण बन गया है। प्रशासन की सख्ती, राजनीतिक दलों की सक्रियता और जनता की उम्मीदें—इन सभी के बीच यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति एक नया मोड़ लेने वाली है। अब सबकी नजरें मतगणना के दिन पर टिकी हैं, जब यह तय होगा कि जनता ने किसे अपना जनादेश सौंपा है और किस दिशा में राज्य की राजनीति आगे बढ़ेगी।

ट्रंप का बड़ा बयान: ईरान समझौते को तैयार, युद्धविराम तोड़ने की जरूरत नहीं

वॉशिंगटन से सामने आए ताजा घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए समझौता करने को बेताब है और फिलहाल हवाई हमलों को फिर से शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि मौजूदा हालात में संघर्ष-विराम तोड़ने की जरूरत नहीं दिखती और कूटनीतिक रास्ते अभी भी खुले हुए हैं।

ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत एक संवेदनशील चरण में है, जिसकी जानकारी सीमित लोगों तक ही है। उन्होंने कहा कि वार्ता की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक नहीं की जा सकती और केवल कुछ चुनिंदा लोग ही इसकी पूरी जानकारी रखते हैं। ट्रंप के इस बयान को ऐसे समय में अहम माना जा रहा है, जब ईरान की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि अमेरिका ने दोबारा हमले किए, तो वह भी जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दोहराया कि दोनों देशों के बीच आठ अप्रैल को हुए युद्धविराम के बाद से स्थिति अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस संघर्ष-विराम को तोड़ने के पक्ष में हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनका यह रुख संकेत देता है कि फिलहाल अमेरिका सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीतिक समाधान पर अधिक जोर देना चाहता है।

ट्रंप ने अपने बयान में यह दावा भी किया कि हालिया सैन्य कार्रवाइयों के बाद ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। उनके अनुसार, ईरान की नौसेना और वायुसेना गंभीर रूप से कमजोर हो चुकी हैं और ड्रोन निर्माण से जुड़े करीब 82 प्रतिशत कारखाने बंद हो गए हैं। इसके अलावा मिसाइल उत्पादन पर भी बड़ा असर पड़ा है और लगभग 90 प्रतिशत तक उत्पादन क्षमता ठप हो चुकी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका की कार्रवाई ने ईरान की परमाणु क्षमता को लगभग समाप्त कर दिया है।

उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर भी ईरान की स्थिति को कमजोर बताते हुए कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी नाकाबंदी के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। उनके अनुसार, तेल निर्यात से होने वाली आय में भारी गिरावट आई है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह बयान स्पष्ट रूप से अमेरिका के दबाव की रणनीति को दर्शाता है।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रंप प्रशासन का एक और अहम पहलू सामने आया है। प्रशासन का तर्क है कि आठ अप्रैल के युद्धविराम समझौते के बाद ईरान के साथ सक्रिय युद्ध समाप्त हो चुका है। इसी आधार पर वह अमेरिकी कांग्रेस से औपचारिक मंजूरी लेने की बाध्यता से बचने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी कानून, विशेष रूप से 1973 का वार पावर्स एक्ट, यह अनिवार्य करता है कि यदि कोई सैन्य कार्रवाई 60 दिनों से अधिक चलती है, तो उसे संसद की मंजूरी प्राप्त करनी होती है।

इस संदर्भ में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी सीनेट के समक्ष अपने बयान में कहा कि युद्धविराम ने प्रभावी रूप से संघर्ष को समाप्त कर दिया है। उनका यह बयान ट्रंप प्रशासन के रुख की पुष्टि करता है और यह संकेत देता है कि अमेरिका फिलहाल इस मामले को युद्ध की श्रेणी में नहीं देख रहा है।

ट्रंप ने अपने बयान में यह भी दावा किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को रोकने में भूमिका निभाई है, जिसमें भारत-पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दे भी शामिल हैं। हालांकि इस दावे पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं, लेकिन ट्रंप लगातार इसे अपनी कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में पेश करते रहे हैं।

कुल मिलाकर, ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर तनावपूर्ण परिस्थितियां बनी हुई हैं। एक ओर जहां ईरान की ओर से कड़ी चेतावनियां दी जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका बातचीत के जरिए समाधान की बात कर रहा है। यह स्थिति दर्शाती है कि दोनों पक्ष अभी भी टकराव से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात पूरी तरह स्थिर नहीं हैं।

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में यह वार्ता किस दिशा में आगे बढ़ती है। क्या दोनों देश किसी स्थायी समझौते तक पहुंच पाएंगे या फिर तनाव दोबारा बढ़ेगा—यह सवाल अभी अनुत्तरित है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि युद्धविराम बरकरार है और दोनों पक्षों के बीच संवाद की संभावना बनी हुई है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है।

मतगणना से पहले बंगाल में सियासी टकराव तेज: सुवेंदु का टीएमसी पर हमला, ममता पर लगाए दबाव के आरोप

कोलकाता में मतगणना से पहले राजनीतिक माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। आरोप-प्रत्यारोप और कड़े बयानों के बीच सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भवानीपुर सीट से उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने साफ कहा कि वे टीएमसी को किसी भी कीमत पर नियमों के दायरे से बाहर नहीं जाने देंगे और मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करेंगे।

यह पूरा विवाद उस समय और बढ़ गया जब ममता बनर्जी कथित तौर पर ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए गुरुवार रात मतगणना केंद्र पहुंच गईं। उनके इस कदम ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। जैसे ही यह खबर सामने आई, भाजपा की ओर से भी त्वरित प्रतिक्रिया देखने को मिली और सुवेंदु अधिकारी के अभिकर्ता तथा वकील सूर्यनील दास समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद वहां दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे की स्थिति बन गई।

शुक्रवार को सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर ममता बनर्जी और सूर्यनील दास एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने दावा किया कि उनके प्रतिनिधि लगातार वहां मौजूद रहकर हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके।

सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री और टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे मतगणना से पहले अनुचित लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, कोई भी व्यक्ति नियमों से बाहर जाकर कुछ नहीं कर पाएगा। उनका कहना था कि जब तक ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर मौजूद रहीं, तब तक उनके सहयोगी ने वहां रहकर यह सुनिश्चित किया कि कोई गलत तरीका न अपनाया जाए। उन्होंने यह भी दोहराया कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होने दिया जाएगा। अपने बयान में सुवेंदु अधिकारी ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ उठाने से बचें। उन्होंने यह संदेश सीधे तौर पर मतदाताओं को संबोधित करते हुए दिया और भरोसा दिलाया कि भवानीपुर सहित पूरे पश्चिम बंगाल में मतगणना पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से होगी। उनके इस बयान को राजनीतिक रूप से काफी आक्रामक माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है।

इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने भी ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री के मतगणना केंद्र पहुंचने को हार के डर से उठाया गया कदम बताया। भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है, और यही वजह है कि अब वे इस तरह के आरोप लगा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता सब कुछ समझ रही है और अब बदलाव तय है।

भट्टाचार्य ने अपने बयान में और भी आगे जाते हुए कहा कि आने वाले समय में राज्य की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि छह महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं बचेगी। उनका यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है और इसे भाजपा के आत्मविश्वास के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि मतगणना से पहले ही बंगाल में सियासी जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक ओर टीएमसी जहां चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रही है, वहीं भाजपा इन आरोपों को निराधार बताते हुए उल्टा टीएमसी पर ही नियमों के उल्लंघन की कोशिश का आरोप लगा रही है। दोनों पक्षों के बीच यह टकराव अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीनी स्तर पर भी इसकी झलक देखने को मिल रही है।

प्रशासन और चुनाव आयोग के लिए भी यह स्थिति चुनौतीपूर्ण बन गई है, क्योंकि उन्हें एक ओर सुरक्षा और शांति बनाए रखनी है, तो दूसरी ओर यह सुनिश्चित करना है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। मतगणना के दिन किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या विवाद से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पहले ही कड़ा कर दिया गया है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत: अग्रिम जमानत मंजूर, आरोपों पर जांच जारी

नई दिल्ली में एक अहम कानूनी घटनाक्रम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जालसाजी और मानहानि से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। यह मामला हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के खिलाफ लगाए गए कथित आरोपों से जुड़ा हुआ है। अदालत का यह फैसला उस समय आया जब एक दिन पहले ही शीर्ष अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा की ओर से यह तर्क रखा गया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप ट्रायल के दायरे में आते हैं और फिलहाल गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ लगाई गई कुछ धाराएं जमानती हैं और जिन धाराओं में जमानत नहीं है, उनमें भी गिरफ्तारी कर अपमानित करना उचित नहीं होगा। उनका यह भी कहना था कि यदि उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जाती, तो गिरफ्तारी से पहले जमानत का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इस पक्ष को मजबूती देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने अदालत में कहा कि इस मामले में हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है और जांच बिना गिरफ्तारी के भी प्रभावी ढंग से की जा सकती है।

मामले की सुनवाई जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चांदुरकर की पीठ के समक्ष हुई, जिसने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना। अदालत ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा था और उसके बाद यह आदेश सुनाया गया, जिसमें पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देकर राहत प्रदान की गई।

दूसरी ओर, असम सरकार की तरफ से इस जमानत का कड़ा विरोध किया गया। सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि पवन खेड़ा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कथित रूप से जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जांच एजेंसियों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि ये दस्तावेज कैसे बनाए गए, इसमें किन लोगों की भूमिका रही और क्या इसमें किसी विदेशी तत्व की भी संलिप्तता है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि एंटीगुआ जैसे देश का संदर्भ दिया गया, जिसे आमतौर पर भगोड़ों के शरणस्थल के रूप में देखा जाता है, और यह आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। उनके अनुसार, पासपोर्ट की कथित कॉपी नकली है और उसमें छेड़छाड़ की गई है, इसलिए इस मामले की गहराई से जांच जरूरी है।

यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह दावा किया कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं और विदेशों में अघोषित संपत्तियां मौजूद हैं। इन आरोपों के बाद उनके खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद असम पुलिस 7 अप्रैल को उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची थी, लेकिन उस समय वह वहां मौजूद नहीं थे।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने फिलहाल पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत जरूर दी है, लेकिन मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जांच प्रक्रिया जारी रहेगी और आरोपों की सत्यता का निर्धारण ट्रायल के दौरान किया जाएगा। इस निर्णय को कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह एक बार फिर इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि गिरफ्तारी हमेशा अंतिम विकल्प होनी चाहिए, विशेष रूप से तब जब जांच बिना हिरासत के भी संभव हो।

राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह मामला काफी संवेदनशील बना हुआ है। एक ओर कांग्रेस इसे अपने नेता के लिए राहत के रूप में देख रही है, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पक्ष इस मामले को गंभीर आरोपों से जोड़कर देख रहा है। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच एजेंसियां किस दिशा में आगे बढ़ती हैं और क्या इस मामले में कोई ठोस सबूत सामने आते हैं।

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न्यायालय तथ्यों और कानून के आधार पर ही निर्णय लेता है, न कि राजनीतिक दबाव या आरोप-प्रत्यारोप के आधार पर। पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत एक अस्थायी राहत है, लेकिन इसके साथ ही यह भी तय है कि उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा और अदालत के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इस मामले का अंतिम निष्कर्ष अब आने वाले कानूनी चरणों पर निर्भर करेगा, जहां साक्ष्य और तर्क दोनों की कसौटी पर पूरे प्रकरण को परखा जाएगा।

संपादकीय

जिंदगी निगलती रफ्तार

देश के नीति-नियंताओं की सोच रही है कि विकास के लिए चौड़ी व रफ्तार वाली सड़कें जीवन रेखा का काम करें। हाल के वर्षों में इसी सोच के साथ राजग सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण युद्ध स्तर पर किया। देश के उत्थान के लिए विकास के बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी। लेकिन विकास की इस उन्नति के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी विसंगति भी सामने आई कि इन पर होने वाली दुर्घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। हादसों का यह सिलसिला लगातार जारी है। सवाल उठता है कि उच्च तकनीक से तैयार आकर्षक व सुविधाजनक एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रियों की सुरक्षा की कसौटी पर खरे क्यों नहीं उतर पा रहे हैं। यूं तो देश की कुल सड़कों में दो फीसदी ही राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, लेकिन देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में इनकी संख्या तीस फीसदी हो गई है। जो हमारी गंभीर चिंता का सबब बन रहा है। ऐसे में आम नागरिकों की इस गहरी चिंता को महसूस करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप किया है। शीर्ष अदालत ने इस संकट पर गहरी चिंता जताते हुए केंद्र व राज्य सरकार तथा इससे संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता के आधार पर सशक्त करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की मान्यता रही है अधिकारियों की उदासीनता व निर्माण से जुड़ी खामियों की वजह से राजमार्ग व एक्सप्रेस-वे दुर्घटना के कारक नहीं बनने चाहिए। इस दिशा में अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मार्ग खतरे का गलियारा न बने। विडंबना यह भी है कि देश में आम लोगों में ट्रैफिक से जुड़ी अनुशासन की सोच पूरी तरह से विकसित नहीं हो पायी है। खुली सड़क मिलते ही रफ्तार तेज होने लगती है, यह जानते हुए कि ये गति हमारी दुर्गति का कारण भी बन सकती है। इसके अलावा तेज स्पीड में भी फोन पर बात करते रहना और शराब पीकर वाहन चलाना भी सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ाने वाला साबित हुआ है। यह विडंबना ही है कि भारत में दुनिया के अन्य विकसित व समकक्ष विकासशील देशों के अनुपात में वाहनों की संख्या तो कम है लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में हम अव्वल हैं। यह आंकड़ा डराता है कि साल भर में होने वाली करीब साढ़े चार लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में हर साल डेढ़ लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा लाखों लोग घायल होते हैं। दुर्भाग्य से लाखों लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवनपर्यंत अपंगता का शिकार हो जाते हैं। विडंबना यह भी कि सड़क दुर्घटनाओं में दम तोड़ने वाले लोगों में बड़ी संख्या युवा आबादी की है। ये युवा आबादी अपने परिवार की कमाई का मुख्य जरिया होती है, उनकी मौत पूरे परिवार को गरीबी की दलदल में धकेल देती है। यहां प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में कमी क्यों नहीं आ रही है। वास्तव में कोशिश होनी चाहिए कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए होने वाले प्रयास जमीनी हकीकत भी बनें, जो वास्तव में राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे को दुर्घटनाओं से निरापद बना सकें। निस्संदेह, चौड़ी व तेज गति देने वाली सड़कें देश के विकास को प्राणवायु देती हैं, लेकिन ये सड़कें यात्रियों की प्राण रक्षा करने वाली भी होनी चाहिए। सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि राजमार्गों पर ढाबे एक निश्चित दूरी पर हों और उनके पास ट्रकों व भारी वाहनों को खड़ा करने का पर्याप्त स्थान हो। साथ ही अक्सर बड़ी दुर्घटना का कारण बनने वाले सड़क पर खड़े वाहनों पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम बने और सख्त जुर्माना तय हो। कायदे से राजमार्गों पर कहीं भी वाहन को खड़ा करने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए। साथ ही सड़क निर्माण में किसी तकनीकी खामी की गुंजाइश न रहे, इसके लिये भी पर्याप्त सतर्कता उपाय किए जाने चाहिए। इन मार्गों पर अंधेरे में भी नजर आने वाले पर्याप्त संकेतक होने चाहिए ताकि वाहन चालकों को किसी तरह का असमंजस राजमार्ग पर चलते हुए न हो। वक्त आ गया है कि देश में दुर्घटनाओं को टालने के लिए आधुनिक यातायात प्रणाली के अनुसंधान व प्रयोग की दिशा में काम किया जाए।

कोशिका स्तर पर जैविक उम्र बढ़ाती गर्मी

> "एक नया अध्ययन बताता है कि बहुत ज्यादा गर्मी कोशिका स्तर पर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में तेजी ला सकती है। यह हमें अच्छी तरह से ज्ञात है कि बहुत अधिक तापमान शरीर पर दबाव डाल सकता है। लेकिन अब इस बात के सबूत बढ़ रहे हैं कि लंबे समय तक गर्मी में रहने से आयु-वृद्धि की प्रक्रिया तेज हो सकती है।

तेजी से गर्म होती दुनिया में गर्मी का मौसम अब ज्यादा सताने लगा है। गर्मी पहले से कहीं ज्यादा लंबी और जानलेवा हो गई है। बहुत ज्यादा गर्मी के स्पष्ट प्रभाव डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और थकावट के रूप में दिखाई देते हैं लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि तेज गर्मी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी तेज कर सकती है। सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया एक नया अध्ययन बताता है कि बहुत ज्यादा गर्मी कोशिका स्तर पर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में तेजी ला सकती है। यह हमें अच्छी तरह से ज्ञात है कि बहुत अधिक तापमान शरीर पर दबाव डाल सकता है। लेकिन अब इस बात के सबूत बढ़ रहे हैं कि लंबे समय तक गर्मी में रहने से आयु-वृद्धि की प्रक्रिया तेज हो सकती है।

किसी व्यक्ति की तारीख के अनुसार गिनी जाने वाली उम्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी जैविक उम्र होती है। यही स्वास्थ्य का असली पैमाना है। जैविक उम्र यह दिखाती है कि हमारी कोशिकाएं, ऊतक और अंग कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। जब जैविक उम्र तिथि आधारित उम्र से ज्यादा होती है, तो बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। अध्ययन की वरिष्ठ लेखक जेनिफर एलशायर का कहना है कि गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों में ठंडे इलाकों के लोगों की तुलना में जैविक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया ज्यादा तेज होती है।

गर्मी और उम्र बढ़ने के बीच संबंध की जांच करने के लिए शोधकर्ताओं ने 56 साल और उससे अधिक उम्र के 3,600 से ज्यादा लोगों के डेटा की जांच की, जो स्वास्थ्य और सेवानिवृत्ति से संबंधित अध्ययन में शामिल थे। वैज्ञानिकों ने छह साल की अवधि में रक्त के नमूने लिए और जीन संबंधी बदलावों का पता लगाने के लिए उनका विश्लेषण किया। ये ऐसे रासायनिक परिवर्तन हैं जो जीन के काम करने के तरीके पर असर डालते हैं। इस क्षेत्र में एक बड़ी प्रक्रिया 'डीएनए मिथाइलेशन' है, जिसमें

एक रसायन डीएनए में जुड़ता है। यह प्रक्रिया आनुवंशिक कोड में बदलाव किए बिना जीन को चालू या बंद कर सकती है।

शोधकर्ताओं ने इन आणविक परिवर्तनों पर नजर रखने के लिए एक जैव-रासायनिक टूल (एपिजेनेटिक घड़ी) का इस्तेमाल किया। यह टूल मिथाइलेशन पैटर्न का पता लगाकर जैविक उम्र का अनुमान लगाता है। शोधकर्ताओं ने 2010 से 2016 तक के पुराने गर्मी सूचकांक डेटा के साथ जैविक उम्र बढ़ने की दरों की तुलना की, जिससे गर्मी और आयु-वृद्धि के बीच एक मजबूत संबंध का पता चला। तापमान और आर्द्रता के मिश्रण से यह तय होता है कि गर्मी कितनी ज्यादा है। बहुत ज्यादा गर्मी को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। सतर्कता स्तर 27 सेल्सियस 32 सेल्सियस तक होता है। बहुत ज्यादा सावधानी वाली श्रेणी 32 सेल्सियस से 40 सेल्सियस तक होती है। सबसे खतरनाक स्तर 40 सेल्सियस से शुरू होता है और 51 सेल्सियस तक जाता है।

इस अध्ययन में यह देखा गया कि हर स्तर की गर्मी के बार-बार संपर्क में आने से जैविक उम्र पर कितना असर पड़ता है। बहुत ज्यादा गर्मी के ज्यादा दिनों का मतलब था कोशिका स्तर पर तेजी से उम्र बढ़ना। कुछ क्षेत्रों में लंबे समय तक भीषण तापमान बना रहता है, और इसका वहां के निवासियों की जैविक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर प्रभाव चौंकाने वाला होता है। बहुत ज्यादा गर्मी अब लोगों को रोजाना के आसान काम भी नहीं करने दे रही है। तेज गर्मी में चलना, सफाई करना या बाहर काम करना मुश्किल होता जा रहा है।

वैज्ञानिकों ने एक अन्य अध्ययन में पाया कि 1950 के दशक से, हर साल उन घंटों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है जब गर्मी सामान्य गतिविधियों के लिए खतरनाक हो जाती है। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और कई दूसरे संगठनों के शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया कि तापमान और आर्द्रता का इंसान के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। नतीजों से पता चलता है कि बहुत ज्यादा गर्मी दैनिक जीवन के लिए, खासकर बुजुर्गों के लिए एक चुनौती बनती जा रही है।

अध्ययन की सह-लेखक जेनिफर वैनोस ने कहा कि गर्मी के बारे में ज्यादातर अध्ययन इस बात पर फोकस करते हैं कि गर्मी कितनी लगती है। नया अध्ययन एक अलग सवाल पूछता है कि इंसान का शरीर उस गर्मी में सुरक्षित रूप से क्या कर सकता है। सिर्फ तापमान मापने के बजाय अध्ययन में यह देखा गया कि गर्मी और आर्द्रता शरीर की खुद को ठंडा करने की क्षमता पर कैसे असर डालती हैं। शरीर आमतौर पर पसीना निकलने से ठंडा होता है। लेकिन ज्यादा नमी इस प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इससे त्वचा से गर्मी को बाहर निकलने में मुश्किल होती है।

शोधकर्ताओं ने एक खास मॉडल का इस्तेमाल करके यह अंदाजा लगाया कि कोई इंसान अलग-अलग मौसम में कितनी गतिविधि सुरक्षित रूप से कर सकता है। यह मॉडल स्टडी करता है कि शरीर वातावरण मिलने वाली से गर्मी और शारीरिक गतिविधि के दौरान पैदा होने वाली गर्मी के बीच कैसे संतुलन बनाता है। अगर शरीर तेजी से गर्मी नहीं निकाल पाता तो शरीर का अंदरूनी तापमान बढ़ जाता है और इससे हीटस्ट्रोक हो सकता है। हल्की गर्मी में हल्के काम शरीर को ज्यादा गर्म किए बगैर सुरक्षित रूप से किए जा सकते हैं लेकिन जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो यह एक्टिविटी असुरक्षित हो जाती है।

टीम ने पाया कि कुछ जगहों पर मौसम साल के सबसे गर्म घंटों में ही ऐसे हालात बना सकता है जो रहने लायक नहीं होते। इन हालात में, छाया में चुपचाप बैठने से भी शरीर का तापमान बढ़ सकता है। शोधकर्ताओं ने 1950 से 2024 तक वैश्विक तापमान और आर्द्रता डेटा का विश्लेषण किया। इससे वैज्ञानिकों को यह ट्रैक करने में मदद मिली कि पिछले 75 सालों में गर्मी के संपर्क में आने का तरीका कैसे बदला है। नतीजे बताते हैं कि खतरनाक गर्मी आम होती जा रही है। 18 से 40 साल के युवा अब बीसवीं सदी के बीच की तुलना में हर साल लगभग दोगुने घंटे ऐसे समय का सामना करते हैं जब गर्मी की वजह से सामान्य गतिविधि असुरक्षित हो जाती है।

वर्ष 1950 और 1970 के दशक के बीच, युवा हर साल लगभग 25 घंटे इस तरह के समय का अनुभव करते थे। आज यह संख्या बढ़कर सालाना लगभग 50 घंटे हो गई है। बुजुर्गों के लिए यह बढ़ोतरी और भी ज्यादा है। पहले, 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को हर साल लगभग 600 घंटे ऐसे समय का अनुभव होता था जब गर्मी की वजह से सामान्य गतिविधि सीमित हो जाती थी। अब यह संख्या बढ़कर हर साल लगभग 900 घंटे हो गई है। बुजुर्गों को ज्यादा खतरा होता है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर को पसीने और स्वस्थ रक्त संचार से खुद को ठंडा रखना मुश्किल हो जाता है। बुजुर्गों का शरीर जवान लोगों की तरह अच्छे से ठंडा नहीं हो पाता।

प्रेरणा

अंतःश्रद्धा का प्रकाश और धर्मतत्व की प्राप्ति

धर्म केवल बाहरी आचरण, रीति-रिवाज या कर्मकांड का विषय नहीं है, बल्कि वह मनुष्य के अंतःकरण में जागृत होने वाली उस गहन भावना का नाम है जिसे श्रद्धा कहा जाता है। जब तक व्यक्ति के भीतर स्थिर, अडिग और निर्मल श्रद्धा नहीं होती, तब तक वह धर्म के वास्तविक तत्व को स्पर्श भी नहीं कर सकता। यही कारण है कि हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने बार-बार इस बात पर बल दिया कि धर्म का आरंभ बाहर से नहीं, भीतर से होता है। मनुष्य की आंतरिक दृढ़ता ही उसे सत्य के मार्ग पर स्थिर रखती है, और यही स्थिरता धीरे-धीरे उसे आत्मतत्व के निकट ले जाती है।

प्राचीन काल में एक अत्यंत रोचक और गूढ़ प्रसंग मिलता है, जिसमें शुकदेव ने अपने पिता और गुरु व्यास से धर्म के गूढ़ रहस्य को जानने की इच्छा प्रकट की। शुकदेव स्वयं अत्यंत विद्वान और आत्मज्ञानी थे, फिर भी उन्होंने यह समझा कि धर्मतत्व केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव और स्थिरता से प्राप्त होता है। जब उन्होंने व्यास से इस विषय में मार्गदर्शन माँगा, तो व्यास ने उन्हें तत्काल उत्तर देने के बजाय राजा जनक के पास जाने का निर्देश दिया। यह निर्देश अपने आप में एक संकेत था कि धर्म का ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि जीवन के व्यवहार और धैर्य में भी छिपा होता है।

शुकदेव आज्ञा का पालन करते हुए राजा जनक के पास पहुँचे। उन्होंने जाकर अपने आगमन की सूचना दी और मिलने की इच्छा प्रकट की। किंतु उन्हें तुरंत भेंट का अवसर नहीं मिला। उत्तर आया कि उन्हें सात दिनों तक प्रतीक्षा करनी होगी। यह सुनकर कोई साधारण व्यक्ति विचलित हो सकता था, उसे अपमान या उपेक्षा का अनुभव हो सकता था, परंतु शुकदेव के भीतर की श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने इसे एक परीक्षा के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने न तो क्रोध किया, न ही असंतोष प्रकट किया, बल्कि बिना किसी सुविधा, आश्रय या विशेष आदर के वे उन सात दिनों तक शांत भाव से प्रतीक्षा करते रहे।

उन सात दिनों का समय केवल बाहरी प्रतीक्षा का नहीं, बल्कि आंतरिक साधना का काल था। शुकदेव के भीतर यह विचार लगातार चलता रहा कि यदि उद्देश्य उच्च है, तो मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ और विलंब भी उसी का एक अंग हैं। जब मनुष्य किसी महान लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो समय-समय पर उसकी परीक्षा अवश्य होती है। यह परीक्षा उसकी योग्यता की नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा की होती है। यदि श्रद्धा कमजोर पड़ जाए, तो मनुष्य मार्ग से भटक जाता है; और यदि श्रद्धा अडिग रहे, तो वही उसे मंजिल तक पहुँचाती है।

सात दिन पूरे होने के बाद अंततः शुकदेव को राजा जनक के दरबार में बुलाया गया। वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ, उन्हें सम्मानपूर्वक आसन दिया गया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। यह परिवर्तन केवल बाहरी व्यवहार का नहीं था, बल्कि यह इस बात का संकेत था कि अब शुकदेव परीक्षा में सफल हो चुके थे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि उनकी श्रद्धा परिस्थितियों के अनुसार बदलने वाली नहीं है, बल्कि वह स्थिर और अटल है।

जब शुकदेव जाने लगे, तब राजा जनक ने उन्हें जो संदेश दिया, वह धर्म के मूल तत्व को अत्यंत सरल शब्दों में प्रकट करता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की श्रद्धा की प्रखरता और शिथिलता ही यह निर्धारित करती है कि वह धर्मतत्व को प्राप्त करेगा या नहीं। यदि श्रद्धा में दृढ़ता है, तो साधक हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और अंततः सत्य को प्राप्त करता है; लेकिन यदि श्रद्धा डगमगा जाती है, तो वह मार्ग में ही रुक जाता है।

यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि धर्म का संबंध केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि धैर्य, सहनशीलता और आंतरिक विश्वास से भी है। आज के समय में भी मनुष्य अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करता है। जब उसे अपने प्रयासों का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, तो वह निराश हो जाता है, क्रोधित हो जाता है या अपने मार्ग से भटक जाता है। परंतु यदि वह शुकदेव की तरह अपनी श्रद्धा को बनाए रखे, तो वह हर कठिनाई को पार कर सकता है।

श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक जागरूक विश्वास है जो अनुभव और समझ पर आधारित होता है। यह वह शक्ति है जो मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब व्यक्ति के भीतर यह भावना होती है कि उसका लक्ष्य सत्य और श्रेष्ठ है, तो वह किसी भी बाधा से नहीं घबराता। यही भावना उसे निरंतर आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। धर्मतत्व की प्राप्ति एक क्षणिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। इसमें समय लगता है, धैर्य की आवश्यकता होती है और कई बार तिरस्कार या उपेक्षा भी सहनी पड़ती है। परंतु जो व्यक्ति इन सबके बावजूद अपनी श्रद्धा को बनाए रखता है, वही अंततः उस परम सत्य को प्राप्त करता है जिसे अमृतत्व कहा गया है। यह अमृतत्व केवल मृत्यु से परे जाने का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस अवस्था का संकेत है जहाँ मनुष्य पूर्ण शांति, संतोष और आत्मबोध को प्राप्त करता है।

इस प्रकार, शुकदेव और राजा जनक का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कोई भी लक्ष्य क्यों न हो, यदि उसके प्रति हमारी श्रद्धा अडिग है, तो सफलता निश्चित है। धर्म का सार यही है कि हम अपने भीतर उस स्थिरता और विश्वास को विकसित करें जो हमें हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखे। जब यह संतुलन प्राप्त हो जाता है, तब मनुष्य न केवल धर्मतत्व को समझता है, बल्कि उसे अपने जीवन में भी उतार पाता है, और यही सच्चे अर्थों में जीवन की पूर्णता है।

अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की सियासी कमर तोड़कर निरंतर आगे बढ़ रही है भाजपा, मजबूत हो रहा एनडीए

भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की सियासी कमर तोड़कर निरंतर आगे बढ़ रही है। इससे भाजपा नीत एनडीए का कुनबा भी लगातार मजबूत हो रहा है। देश के मतदाता भी जातीय और भाषाई प्रतिद्वंद्विता से ऊपर उठकर धुर मुस्लिम तुष्टिकरण की चुनावी राजनीति की बखिया उघेड़ रहे हैं, जबकि फ्रीबिज की घोषणाओं पर अब भी मतदाता फिदा हैं। 29 अप्रैल को देश के पांच राज्यों—पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी—के विधानसभा चुनावों के जो एग्जिट पोल आए, उससे भी इसी बात के संकेत मिल रहे हैं। इससे भाजपा और उसके एनडीए साथियों की बल्ले बल्ले है। वैसे तो अंतिम परिणाम 4 मई को ही आएंगे, लेकिन अब मीडिया की सजगता से अधिकांश एग्जिट पोल के औसत सत्य के निकट होते हैं।लिहाजा यदि एग्जिट पोल सही होते हैं तो इससे जो बड़ा राजनीतिक निष्कर्ष निकलकर सामने आया है, वह यह है कि देश की राजनीति में भाजपा के बेहतर प्रदर्शनों के बावजूद क्षेत्रीय दल अभी भी मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि देश पर 12 वर्षों से शासन कर रही भाजपा, बहुतेरे प्रशासनिक मामलों में कांग्रेस और समाजवादियों की राजनीतिक नकल करके और जरूरत के मुताबिक हिंदुत्व के चोलों को उतार फेंककर उन राज्यों में भी अव्वल प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है, जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम और ईसाई वोट अबतक निर्णायक रहते आये हैं।

ऐसा उलटफेर करके भाजपा/एनडीए कई राज्यों में अपनी पकड़ बढ़ाते दिख रहे हैं। खासकर उत्तरपूर्वी, दक्षिणी और जम्मूकश्मीर जैसे राज्यों में, जो उसकी बड़ी सफलता है। इससे आम चुनाव 2029 में भी उसे राजनीतिक फायदा मिलेगा, क्योंकि भाजपा समेत एनडीए को इससे नई सोच और नई ऊर्जा मिलेगी। जबकि इंडिया गठबंधन की आपसी रस्साकशी उन्हें 2024 की आंशिक सफलता के बाद निरंतर कमजोर करते हुए रसातल की ओर ले जा रही है। इससे कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी को राजनीतिक सबक लेनी होगी, क्योंकि वर्ष 2027 और 2028 में भी दर्जनाधिक राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

यदि राजनीतिक बारीकीपूर्वक इन एग्जिट पोल्स से संकेतों को पढ़ा जाए तो स्पष्ट दिखाई दे रहा हैं कि उत्तर भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में मजबूत सियासी पैठ बना चुकी भाजपा अब उत्तर-पूर्व समेत पूर्वी भारत में अपना विस्तार बनाए हुए है। जबकि दक्षिण भारत में भी अपने विरोधियों को राजनीतिक रूप से तोड़ने में वह सफल हो चुकी है। तमिलनाडु में डीएमके और केरल में एलडीएफ का कमजोर होकर सत्ता गंवाने की ओर बढ़ना यह सियासी चुगली कर रहा है कि जल्द ही भाजपा दक्षिण भारत में भी उसी तरह का करिश्मा करेगी, जैसा कि उसने उत्तर-पूर्व के असम और त्रिपुरा में किया है, जबकि पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल में करने जा रही है। इसी प्रकार तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना आदि उसकी पकड़ में जल्द आएंगे। वहीं कर्नाटक में तो वह मजबूत है ही और आंध्रप्रदेश में एनडीए की सरकार है।

यह बात दीगर है कि अपने सियासी गर्दिश के दिनों में भी कांग्रेस दक्षिण भारत, खासकर केरल में पुनर्जीवन के संकेत दे रही है। ऐसा पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के पुनः कांग्रेस के खेमे में सटने से हुआ। वहीं, क्षेत्रीय दल—डीएमके, टीएमसी आदि—अब भी अपने-अपने राज्यों में थोड़ा कमजोर होने के बावजूद निर्णायक बने हुए दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा, 2029 लोकसभा चुनाव की दिशा में ये चुनाव "राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय राजनीति" की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। दक्षिण भारत में भाजपा अभी भी पूर्ण प्रभुत्व से दूर दिख रही है, जबकि बंगाल उसका सबसे बड़ा विस्तार क्षेत्र बना हुआ है। पुडुचेरी में भी एनडीए मजबूत हुआ है।

चूंकि 2027 और 2028 में भी कई महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिन पर इन पांच राज्यों के चुनावी फलाफल का असर पड़ेगा। 2027 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे अहम राज्य शामिल हैं। वहीं, 2028 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, उनमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम जैसे महत्वपूर्ण राज्य शामिल हैं। चूंकि इन चुनावों की अंतिम तिथियाँ भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार तय होंगी, इसलिए कार्यक्रम में बदलाव संभव है।

पहला, असम में भाजपा मजबूत हुई है, क्योंकि एग्जिट पोल भाजपा-एनडीए को लगातार तीसरी बार स्पष्ट बहुमत देते दिख रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि हिमंता विश्व सरमा (Himanta Biswa Sarma) की नेतृत्व शैली और भाजपा का पूर्वोत्तर मॉडल अभी भी प्रभावी है।

दूसरा, भाजपा की रणनीति से पुडुचेरी में भी एनडीए को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल एनडीए की वापसी दिखा रहे हैं। यहां भाजपा ने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर अपना आधार मजबूत किया है। तीसरा, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर के बीच भाजपा को बढ़त मिलने के स्पष्ट आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि अधिकांश एग्जिट पोल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच बेहद करीबी मुकाबला दिखाया गया है। वहीं कुछ सर्वे यानी 5 में से 4 भाजपा को सीधी बढ़त दे रहे हैं, जबकि कुछ ममता बनर्जी की वापसी बता रहे हैं। इसका मतलब है कि बंगाल में सत्ता विरोधी लहर और ध्रुवीकरण दोनों साथ-साथ काम कर रहे हैं। चूंकि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत लाखों वोटरों के नाम हटाने को लेकर विवाद है, जिसे भाजपा ने बोगस वोट हटाने के रुप में सही ठहराया है, जबकि टीएमसी ने इसे अपने वोटरों को हटाने की साज़िश बताया है। रुझानों के मुताबिक, महिलाओं ने ममता बनर्जी पर पुनः भरोसा जताया है,जो टीएमसी की बड़ी ताकत है।

अभियान

रात का पीपल: आस्था, अनुभव और विज्ञान के बीच छिपी सच्चाई

गांव की गर्मियों की रातों का अपना एक अलग ही आकर्षण होता है—खुला आसमान, टिमटिमाते तारे, ठंडी हवा और पेड़ों की छांव में बैठकर मिलने वाला सुकून। ऐसे वातावरण में अक्सर लोग पेड़ों के नीचे बैठकर देर तक बातें करते हैं या विश्राम करते हैं। लेकिन जैसे ही बात पीपल के पेड़ की आती है, दादी-नानी की आवाज़ तुरंत सुनाई देती है—"रात में पीपल के नीचे मत बैठो, भूत पकड़ लेगा।" यह वाक्य सुनते ही बचपन में मन में एक अजीब सा डर घर कर जाता था। परंतु जैसे-जैसे समझ बढ़ती है, यह जिज्ञासा भी जन्म लेती है कि आखिर इस चेतावनी के पीछे क्या सच है। क्या यह केवल एक अंधविश्वास है, या फिर इसमें कोई गहरी परंपरा, अनुभव और विज्ञान छिपा हुआ है?

भारतीय संस्कृति में पीपल का पेड़ केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि आस्था और जीवन का प्रतीक माना गया है। इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति से जुड़ा संबंध गौतम बुद्ध के जीवन से भी इस वृक्ष को विशेष बनाता है। इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, उसकी परिक्रमा की जाती है और उसे जीवनदायी शक्ति के रूप में सम्मान दिया जाता है। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और आज भी समाज में उतनी ही श्रद्धा के साथ निभाई जाती है।

लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है और अंधेरा घिरने लगता है, वही पवित्र पीपल रहस्यमयी और डरावना प्रतीत होने लगता है। लोककथाओं और बुजुर्गों की कहानियों में यह बताया जाता रहा है कि रात के समय पीपल के पेड़ के आसपास नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। दादी-नानी बच्चों को डराने के लिए कहती थीं कि वहां भूत-प्रेत रहते हैं, जो अकेले बैठे व्यक्ति को पकड़ सकते हैं। पहली नज़र में यह सब अंधविश्वास लगता है, लेकिन यदि इसे गहराई से समझा जाए, तो इसके पीछे सामाजिक सुरक्षा और व्यवहारिक समझ का एक मजबूत आधार दिखाई देता है।

पुराने समय में गांवों में बिजली की सुविधा नहीं होती थी। रात का अंधेरा घना और गहरा होता था, जिसमें दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। ऐसे में बाहर निकलना अपने आप में जोखिम भरा होता था। पीपल के पेड़ आमतौर पर गांव के किनारे या सुनसान स्थानों पर होते थे, जहां रात में जाना खतरनाक हो सकता था। वहां सांप, बिच्छू या अन्य जीव-जंतु हो सकते थे, जो अंधेरे में आसानी से दिखाई नहीं देते। बच्चों और युवाओं को इन खतरों से बचाने के लिए बुजुर्गों ने एक सरल और प्रभावी तरीका अपनाया—डर की कहानियां। "भूत पकड़ लेगा" जैसी चेतावनी ने बच्चों को स्वाभाविक रूप से उस स्थान से दूर रखा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की।

इसके साथ ही एक वैज्ञानिक कारण भी इस मान्यता के पीछे छिपा हुआ है। दिन के समय पेड़-पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही कारण है कि पेड़ों के आसपास दिन में वातावरण ताजगी भरा और स्वच्छ महसूस होता है। पीपल का पेड़ इस मामले में विशेष माना जाता है, क्योंकि यह लंबे समय तक ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

लेकिन रात के समय, जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। इस समय पेड़ भी अन्य जीवों की तरह श्वसन करते हैं, यानी वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया सामान्य और प्राकृतिक है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक घने पेड़ के नीचे बैठा रहे, तो उसे हल्की घुटन या असहजता महसूस हो सकती है। पुराने समय में लोग इस वैज्ञानिक तथ्य को समझ नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने इसे अलौकिक शक्तियों से जोड़ दिया।

इसके अलावा, पीपल के पेड़ की बनावट भी इसे रहस्यमयी बनाती है। इसकी पत्तियां लगातार हिलती रहती हैं, चाहे हवा बहुत हल्की ही क्यों न हो। रात के सन्नाटे में जब ये पत्तियां सरसराती हैं, तो एक अजीब सी आवाज़ उत्पन्न होती है, जो सुनने में कई बार डरावनी लगती है। यदि आसपास कोई और व्यक्ति न हो और अंधेरा गहरा हो, तो यह आवाज़ किसी को भी विचलित कर सकती है। पुराने समय में जब प्राकृतिक घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने के साधन सीमित थे, तब ऐसी आवाज़ों को भूत-प्रेत से जोड़ना स्वाभाविक था।

रात के समय पीपल के नीचे मच्छरों और कीट-पतंगों की संख्या भी अधिक होती है। ये छोटे जीव न केवल परेशानी पैदा करते हैं, बल्कि कई बार बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां मच्छरों के माध्यम से फैलती हैं, और पुराने समय में इनसे बचाव के साधन भी सीमित थे। इसलिए यह आवश्यक था कि लोग रात में ऐसे स्थानों से दूर रहें, जहां इनका खतरा अधिक हो। बुजुर्गों ने इसे एक नियम के रूप में स्थापित किया और धीरे-धीरे यह परंपरा बन गई।

यह पूरी परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज केवल धार्मिक या भावनात्मक दृष्टिकोण से नहीं सोचते थे, बल्कि उनके निर्णयों में व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और अनुभव का गहरा प्रभाव होता था। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर ऐसे नियम बनाए, जो समाज को सुरक्षित और संतुलित बनाए रखने में सहायक थे। भले ही उन्होंने इन नियमों को वैज्ञानिक भाषा में व्यक्त नहीं किया, लेकिन उनके पीछे का तर्क अत्यंत सशक्त था।

आज के समय में, जब हमारे पास विज्ञान और तकनीक की बेहतर समझ है, तो हमें इन मान्यताओं को अंधविश्वास कहकर खारिज करने के बजाय उनके पीछे छिपे ज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह समझ हमें न केवल अपने अतीत से जोड़ती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में सावधानी और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। दादी-नानी की बातें केवल कहानियां नहीं थीं, बल्कि वे जीवन के अनुभवों का सार थीं, जिन्हें उन्होंने सरल भाषा में अगली पीढ़ी तक पहुंचाया।

इसका यह अर्थ नहीं है कि पीपल का पेड़ किसी प्रकार से हानिकारक है। इसके विपरीत, यह एक अत्यंत उपयोगी और पर्यावरण के लिए लाभकारी वृक्ष है। दिन के समय इसकी छांव में बैठना, ध्यान करना या विश्राम करना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। यह पेड़ हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसे सम्मान देने की प्रेरणा देता है।

अंततः, "पीपल के नीचे मत बैठो, भूत पकड़ लेगा" जैसी चेतावनी एक गहरी सीख छुपाए हुए है। यह हमें यह बताती है कि हर परंपरा के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है—चाहे वह धार्मिक हो, सामाजिक हो या वैज्ञानिक। जब हम इन कारणों को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे पूर्वजों की सोच कितनी गहरी और दूरदर्शी थी। इसलिए अगली बार जब यह बात सुनाई दे, तो उसे केवल एक डरावनी कहानी के रूप में न लें, बल्कि उसे एक संदेश के रूप में समझें—सावधानी का, सुरक्षा का और प्रकृति के नियमों के प्रति सम्मान का। यही समझ हमें अंधविश्वास से ज्ञान की ओर और डर से जागरूकता की ओर ले जाती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

लोभ की हैवानियत: कड़े के लिए बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या, पैरों तक को नहीं छोड़ा

गुजरात के छोटा उदेपुर जिले से सामने आई एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। नसवाड़ी तालुका के गढ़ बोरियाद गांव में जो हुआ, वह केवल एक हत्या नहीं बल्कि इंसानियत की सीमाओं को पार कर देने वाली दरिंदगी का उदाहरण बन गया है। 75 वर्षीय वृद्ध महिला दशरी भीला भील, जो अपने कच्चे घर में अकेली रहती थीं, अपराधियों की क्रूरता का शिकार बन गईं। बदमाशों ने न केवल उनकी हत्या की, बल्कि उनके पैरों को काटकर चांदी के कड़े लूट लिए—ऐसी बर्बरता जिसने पूरे गांव में भय, गुस्सा और असहायता का माहौल पैदा कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना रात के अंधेरे में उस समय घटी जब दशरी भील अपने घर में अकेली थीं। आदिवासी समाज में पैरों में भारी चांदी के कड़े पहनने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, और दशरी भील भी करीब एक किलो वजन के चांदी के कड़े पहने हुए थीं। इन कड़ों की कीमत लगभग ढाई लाख रुपये बताई जा रही है। यही लालच अपराधियों को इस हद तक ले गया कि उन्होंने पहले वृद्धा के सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी और फिर उनके पैरों को काटकर कड़े निकाल लिए।

घटना का खुलासा बेहद दर्दनाक तरीके से हुआ। मृतका का बेटा अतुल भील, जो रोज की तरह काम पर गया हुआ था, जब शाम को घर लौटा तो पड़ोस की महिलाओं ने उसे बताया कि उसकी मां सुबह से घर से बाहर नहीं निकली हैं। यह सुनकर उसे कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ। जब वह घर के अंदर गया, तो सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसकी मां खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थीं, और उनके शरीर के साथ जो किया गया था, उसे देखकर कोई भी सामान्य इंसान सिहर उठे।

इस घटना ने न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि पूरे गांव के लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है। गढ़ बोरियाद जैसे शांत इलाके में इस तरह की वारदात ने लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके गांव में इस तरह की क्रूरता देखने को मिलेगी। लोग अब रात में बाहर निकलने से डर रहे हैं और अपने घरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

सूचना मिलते ही नसवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या और लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और संभावित सुराग जुटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और उन्हें कानून के अनुसार सख्त सजा दिलाई जाएगी।

मृतका के बेटे अतुल भील ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसका कहना है कि उसकी मां ने किसी का क्या बिगाड़ा था, जो उन्हें इतनी दर्दनाक मौत दी गई। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे हैं। यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है—क्या कुछ पैसों के लिए इंसान इतना निर्दयी हो सकता है?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं केवल कानून-व्यवस्था की कमजोरी का परिणाम नहीं होतीं, बल्कि यह समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता और लालच का भी संकेत हैं। जब इंसान पैसे और लालच के आगे इंसानियत को भूल जाता है, तब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। यह जरूरी है कि समाज और प्रशासन दोनों मिलकर ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं और लोगों में जागरूकता बढ़ाएं।

इस घटना ने एक और गंभीर पहलू को भी उजागर किया है—अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं और अपराधियों के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन उनके लिए विशेष सुरक्षा उपाय करे और समाज भी उनकी देखभाल के प्रति संवेदनशील बने।

फिलहाल, पुलिस की जांच जारी है और पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लेकिन इस घटना का जो दर्द और जो डर लोगों के मन में बैठ गया है, उसे खत्म होने में समय लगेगा। गढ़ बोरियाद गांव के लोग आज भी उस खौफनाक रात को याद कर सहम जाते हैं, जब इंसानियत शर्मसार हो गई और एक बुजुर्ग महिला को केवल कुछ चांदी के कड़ों के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी।

यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। क्या हम केवल भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हुए अपनी मानवता खोते जा रहे हैं? अगर इसका जवाब 'हाँ' है, तो यह चिंता का विषय है और हमें इसे बदलने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। कानून अपना काम करेगा, अपराधियों को सजा मिलेगी, लेकिन सबसे जरूरी है कि समाज अपनी संवेदनशीलता को बचाए रखे, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोहराई न जाएं।

अहमदाबाद मण्डल पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का आयोजन
WRWWO-अहमदाबाद द्वारा 30 रेलकर्मी सम्मानित

दिनांक 1 मई 2026 अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO), अहमदाबाद मंडल द्वारा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल के विभिन्न विभागों के 30 रेलकर्मियों को प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया एवं उनके कठोर परिश्रम, लगन एवं निष्ठा पूर्ण कार्यों की सराहना की गई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर WRWWO अहमदाबाद मंडल की अध्यक्षा श्रीमती शेफाली गुप्ता ने सभी रेलकर्मियों को मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय रेल, जो देश की जीवन रेखा है, उसकी मजबूती और सफलता के पीछे लाखों कर्मचारियों का अथक परिश्रम निहित है। उन्होंने कहा कि ट्रैकमैन, गार्ड, लोको पायलट, तकनीकी कर्मचारी या स्टेशन स्टाफ—हर कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाता है। मजदूर दिवस हमें यह संदेश देता है कि हर श्रमिक का योगदान अमूल्य है और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने अपने संबोधन में रेलकर्मियों की लगन एवं समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि लाइन पर कार्य करने वाले कर्मचारी हर मौसम में बिना थके अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल केवल पटरियों और ट्रेनों का नेटवर्क नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों की मेहनत, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है। दिन-रात, गर्मी-बरसात हर परिस्थिति में रेलकर्मी अपनी सेवाएं देकर देश की गति को बनाए रखते हैं।

इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री विकास गढ़वाल, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री सिद्धार्थ सहित अन्य अधिकारीगण, महिला कल्याण संगठन की सदस्याएं, रेलवे यूनियन एवं एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।

सूरत की सियासत में नई हलचल: महिला मेयर के चयन को लेकर भाजपा में तेज हुई 'सेंस' कवायद

सूरत नगर निगम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब शहर के नए नेतृत्व के चयन की प्रक्रिया में पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। 115 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ लगातार सातवीं बार सत्ता में लौटी भाजपा के सामने अब सबसे अहम सवाल यही है कि शहर का अगला मेयर कौन होगा। गजट जारी होने के साथ ही नए कार्यकाल की औपचारिक शुरुआत होगी और इसके साथ सूरत को एक नई महिला मेयर मिलने जा रही है, क्योंकि इस बार यह पद महिला (जनरल) वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।

यह आरक्षण अपने आप में राजनीतिक समीकरणों को बदल देने वाला साबित हो रहा है। सूरत नगर निगम के इतिहास में यह छठी बार होगा जब कोई महिला मेयर पद संभालेगी। खास बात यह है कि इस बार चुनाव में भाजपा की 58 महिला पार्षद जीतकर आई हैं, जिससे दावेदारों की संख्या भी बढ़ गई है और प्रतिस्पर्धा बेहद रोचक हो गई है। पार्टी के भीतर कई नाम चर्चा में हैं, जिनमें अनुभवी पार्षदों से लेकर नए चेहरों तक की दावेदारी देखी जा रही है। यही वजह है कि इस बार मेयर का चयन केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि गहन विचार-विमर्श और रणनीतिक संतुलन का परिणाम होगा।

भाजपा ने इस चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और संतुलित बनाने के लिए अपनी पारंपरिक 'सेंस प्रक्रिया' को अपनाया है। यह प्रक्रिया 2 मई 2026 को सुबह 10 बजे उधना स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित की जा रही है। इसमें पार्टी के ऑब्जर्वर, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सांसद, वर्तमान विधायक और शहर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। वे सभी चुने हुए पार्षदों और प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से राय लेकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच किस नाम पर सबसे अधिक सहमति बन रही है।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल नामों की सूची तैयार करना नहीं है, बल्कि संगठन के भीतर संतुलन बनाए रखना भी है। भाजपा के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वह इतने बड़े जनादेश के बाद भी आंतरिक असंतोष को जन्म न दे। पार्टी नेतृत्व यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मेयर का चयन ऐसा हो जो सभी गुटों को संतुष्ट कर सके और शहर के विकास एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ा सके। सूरत जैसे तेजी से विकसित होते शहर में मेयर की भूमिका केवल औपचारिक नहीं होती, बल्कि वह शहर की प्रशासनिक दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

'सेंस प्रक्रिया' के बाद पार्टी एक पैनल तैयार करेगी, जिसमें संभावित नामों को शामिल किया जाएगा। इसी पैनल के आधार पर मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन, रूलिंग पार्टी लीडर और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। यह पूरा ढांचा सूरत नगर निगम के अगले पांच वर्षों के प्रशासनिक ढांचे को निर्धारित करेगा। इसलिए हर पद पर सही व्यक्ति का चयन पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार महिला नेतृत्व को लेकर भाजपा एक मजबूत संदेश देना चाहती है। सूरत जैसे औद्योगिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण शहर में महिला मेयर का चयन न केवल सामाजिक संतुलन को दर्शाएगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि पार्टी महिला सशक्तिकरण के अपने एजेंडे को गंभीरता से लागू कर रही है। इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि पार्टी ऐसे चेहरे को आगे लाना चाहती है, जो प्रशासनिक अनुभव के साथ-साथ जनसंपर्क में भी मजबूत हो। भाजपा के लिए यह भी जरूरी है कि वह अपने विकास मॉडल को बनाए रखे। सूरत को देश के सबसे तेज़ी से विकसित होते शहरों में गिना जाता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता और उद्योग के क्षेत्र में लगातार प्रगति हुई है। ऐसे में नया मेयर इस विकास की गति को बनाए रखने और नई योजनाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभाएगा। पार्टी यह भी ध्यान रख रही है कि चयनित उम्मीदवार में नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता और टीम को साथ लेकर चलने की क्षमता हो।

दूसरी ओर, पार्टी के भीतर चल रही यह प्रतिस्पर्धा यह भी दर्शाती है कि भाजपा के पास नेतृत्व के लिए पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं। हालांकि, यही स्थिति कभी-कभी चुनौती भी बन जाती है, क्योंकि हर दावेदार अपने समर्थन के साथ आता है और उसे संतुष्ट करना आसान नहीं होता। ऐसे में 'सेंस प्रक्रिया' के जरिए पार्टी एक संतुलित और सर्वसम्मत निर्णय तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

आने वाले कुछ दिन सूरत की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। मेयर के नाम की घोषणा के साथ ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और वह शहर के विकास के लिए किस प्रकार का नेतृत्व चुन रही है। फिलहाल, सभी की निगाहें इस प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस महिला नेता को सूरत की कमान सौंपी जाती है।

इस पूरे घटनाक्रम से यह भी साफ है कि चुनाव जीतना एक चरण होता है, लेकिन उस जीत को सही दिशा देना असली चुनौती होती है। भाजपा के लिए सूरत में यह वही क्षण है, जहां उसे अपने संगठनात्मक कौशल और राजनीतिक समझ का प्रदर्शन करना है, ताकि आने वाले पांच वर्षों में शहर की प्रगति और जनता का विश्वास दोनों बरकरार रह सके।

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस, सूरत

सूरत में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का भव्य प्रारंभ
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा एग्जीबिशन का उद्घाटन

- ऑरो यूनिवर्सिटी में औद्योगिक विकास, ग्रीन एनर्जी, कृषि और सेवा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को प्रतिबिंबित करती विशाल प्रदर्शनी का उद्घाटन
- मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का उद्घाटन कर विभिन्न स्टॉलों का दौरा कर प्रत्यक्ष निरीक्षण किया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ से पूर्व ऑरो यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल एग्जीबिशन का विधिवत् उद्घाटन किया।

इस अवसर पर राज्य के औद्योगिक विकास, कृषि प्रगति, ग्रीन एनर्जी और सेवा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को प्रतिबिंबित करती हुई एक विशाल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।

मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी के विभिन्न पवेलियन और स्टॉलों का दौरा कर उद्योगपतियों और स्टार्टअप प्रतिनिधियों से चर्चा की। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी इकाइयों, कृषि में आधुनिक पद्धतियों और सेवा क्षेत्र के विकसित हो रहे मॉडलों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने राज्य के विकास में निजी क्षेत्र, उद्योगपतियों और युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रोत्साहित किया।

गुजरात देश के 'ग्रोथ इंजन' के रूप में आगे बढ़ रहा है, तब राज्य सरकार द्वारा 'वाइब्रेंट गुजरात' के वैश्विक विजन को अधिक व्यापक बनाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का नूतन दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस पहल के माध्यम से राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में मौजूद विकास के अवसरों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सूरत में आयोजित इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में दक्षिण गुजरात के सूरत सहित 6 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें उद्योग, कृषि, एमएसएमई और सेवा क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य रीजनल इन्डस्ट्री ग्रोथ को गति देना, निवेशकों को आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना है। इस प्रदर्शनी को औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कृषि, फूड प्रोसेसिंग और सेवा क्षेत्र जैसे मुख्य विभागों में विभाजित किया गया है। इस प्रदर्शनी में नई उत्पादों, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, स्टार्टअप इनोवेशन और सरकारी योजनाओं का भी प्रदर्शन किया गया है।

विशेष रूप से ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में सोलर और विंड एनर्जी से संबंधित परियोजनाएं आकर्षण का केंद्र रहीं। इसके अलावा, गुजरात की पहचान को दर्शाने वाला 'मैंगो फेस्टिवल' भी आयोजित किया गया, जिसमें दक्षिण गुजरात में उगाई जाने वाली आम की विभिन्न किस्मों को प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ट्रेड फेयर का भी शुभारंभ किया और प्रदर्शनी से उत्पन्न होने वाली व्यावसायिक संभावनाओं पर संतोष व्यक्त किया। इस प्रकार की क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस राज्य के संतुलित और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी. आर पाटिल, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, विधायक, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के अग्रणी तथा देश-विदेश के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे विभिन्न गंतव्यों के बीच चलाएगी तीन स्पेशल ट्रेनें

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा ग्रीष्मकालीन सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न गंतव्यों के बीच विशेष किराए पर तीन स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें एक पूर्णतः अनारक्षित स्पेशल ट्रेन भी शामिल है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेन संख्या 09079/09080 मुंबई सेंट्रल – इंदौर एसी सुपरफास्ट स्पेशल (द्वि-साप्ताहिक)

ट्रेन संख्या 09079 मुंबई सेंट्रल – इंदौर स्पेशल प्रत्येक रविवार एवं मंगलवार को 23:20 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 13:00 बजे इंदौर पहुंचेगी। यह ट्रेन 03 मई, 2026 से 28 जून, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09080 इंदौर–मुंबई सेंट्रल स्पेशल प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को 17:00 बजे इंदौर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 07:10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन 04 मई, 2026 से 29 जून, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, दाहोद, रतलाम एवं उज्जैन स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 3-टियर तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09081/09082 मुंबई सेंट्रल – वटवा एसी सुपरफास्ट स्पेशल (साप्ताहिक)

ट्रेन संख्या 09081 मुंबई सेंट्रल – वटवा स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को 23:20 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 07:20 बजे वटवा पहुंचेगी। यह ट्रेन 07 मई, 2026 से 25 जून, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09082 वटवा – मुंबई सेंट्रल स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को 22:40 बजे वटवा से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 07:10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन 08 मई, 2026 से 26 जून, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत एवं वडोदरा स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 3-टियर तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

3. ट्रेन संख्या 09157/09158 बांद्रा टर्मिनस – गोरखपुर – बोरीवली पूर्णतः अनारक्षित स्पेशल

ट्रेन संख्या 09157 बांद्रा टर्मिनस – गोरखपुर स्पेशल रविवार, 03 मई, 2026 को 00:30 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 17:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09158 गोरखपुर–बोरीवली स्पेशल सोमवार, 04 मई, 2026 को 20:30 बजे गोरखपुर से प्रस्थान करेगी और बुधवार को 11:30 बजे बोरीवली पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, बयाना, भरतपुर, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, बरेली सिटी, इज्जतनगर, पीलीभीत, मैलानी, सीतापुर, बुढ़वल, गोंडा, बस्ती एवं खलीलाबाद स्टेशनों पर ठहरेगी। ट्रेन संख्या 09157 का बोरीवली स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव होगा।

इस ट्रेन में जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09079 एवं 09080 की बुकिंग 02.05.2026 से तथा ट्रेन संख्या 09081 एवं 09082 की बुकिंग 03.05.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। ट्रेनों के समय, ठहराव एवं संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

Beat The Heat पहल, यात्रियों ने कहा थैंक्यू

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा इस समर सीजन में गर्मी से राहत के लिए "Beat the Heat" पहल शुरू की गई है। यात्रियों ने वडोदरा मंडल की इस पहल की विशेष सराहना की है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री नरेन्द्र कुमार ने इस पहल के बारे में बताया कि पिछले वर्ष में इस अभियान की सफ़लता के बाद इस वर्ष भी वडोदरा मंडल यात्रियों की सेवा में Beat The Heat 2.0 के जरिए उपलब्ध है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान सामान्य श्रेणी के यात्रियों के आराम और कल्याण पर विशेष ध्यान देना था। अभियान के दौरान स्टेशनों और ट्रेनों में कर्मचारियों तथा एनजीओ टीमों के सक्रिय समन्वय से इलेक्ट्रोलाइट युक्त संतरे का जूस, पेयजल और अन्य हाइड्रेशन सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं। इस प्रयास से विशेष रूप से अनारक्षित कोचों में यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिली। उनके अनुसार इस पहल को गर्मी के सीज़न में लगातार 30 दिनों तक सफलतापूर्वक जारी रखा जायेगा।

भावनगर मंडल द्वारा सघन टिकट जांच अभियान में उल्लेखनीय सफलता, अप्रैल 2026 में 91.32 लाख का राजस्व अर्जित

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा अप्रैल 2026 के दौरान चलाए गए सघन टिकट जांच अभियान में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। इस अवधि में कुल 11,943 यात्री अनियमित यात्रा करते हुए पाए गए, जिनमें से 5,283 यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए गए। इन सघन जांच कार्रवाइयों से मंडल ने अप्रैल माह में 91.32 लाख का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष के अप्रैल माह के 77.22 लाख की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। यह पिछले दो वर्षों में किसी एक माह के दौरान टिकट जाँच की अधिकतम आय है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह उत्कृष्ट प्रदर्शन मंडल की प्रभावी निगरानी व्यवस्था, सतत जांच अभियानों तथा यात्री सेवाओं के सुव्यवस्थित प्रबंधन का परिणाम है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें और रेलवे के नियमों का पालन करें।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के समग्र प्रदर्शन की बात करें तो भावनगर मंडल ने उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करते हुए कुल 1345.63 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.7% अधिक है।

टिकट जांच अभियान के अंतर्गत भी वर्ष 2025–26 में ऐतिहासिक सफलता दर्ज की गई। इस अवधि में टिकट जांच से 7.15 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 48.8% अधिक होने के साथ-साथ अब तक का सर्वाधिक है। यह उपलब्धि टिकट जांच स्टाफ की सतर्कता, नियमितता एवं सघन निरीक्षण का प्रत्यक्ष परिणाम है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर सभी संबंधित कर्मचारियों की सराहना की है तथा भविष्य में भी इसी प्रकार सघन टिकट जांच अभियान चलाकर राजस्व वृद्धि एवं अनियमित यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने का संकल्प दोहराया है।

पश्चिम रेलवे का राम मंदिर और जोगेश्वरी स्टेशनों के बीच मेजर ब्लॉक

पश्चिम रेलवे द्वारा मेट्रो लाइन-6 के स्टील गर्डरों के लॉन्चिंग कार्य के लिए उपनगरीय खंड पर शनिवार/रविवार, अर्थात 2/3 मई, 2026 की मध्यरात्रि को राम मंदिर और जोगेश्वरी स्टेशनों के बीच मेजर ब्लॉक लिया जाएगा।

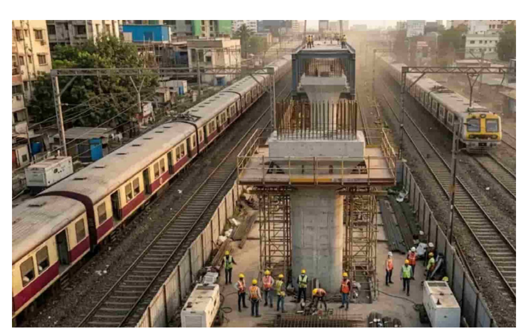

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह ब्लॉक छठी लाइन पर 2 मई, 2026 को 21:30 बजे से 3 मई, 2026 को 07:30 बजे तक कुल 10 घंटे के लिए लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अप फास्ट लाइन तथा पाँचवी लाइन पर 01:00 बजे से 04:00 बजे तक ब्लॉक लिया जाएगा। ब्लॉक अवधि के दौरान छठी लाइन की सभी ट्रेनें बोरीवली और अंधेरी के बीच अप फास्ट लाइन पर चलाई जाएँगी तथा कुछ अप एवं डाउन उपनगरीय सेवाएँ निरस्त रहेंगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी सभी उपनगरीय स्टेशनों पर उपलब्ध है। इसके अलावा, ट्रेन संख्या 19038 बरौनी–बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस सूरत और बोरीवली के बीच लगभग 30 मिनट रेगुलेट होगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त व्यवस्था को ध्यान में रखें।

पश्चिम रेल्वे

सामग्री प्रबंधन विभाग

विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति

ई-प्रोक्योरमेंट टेंडर सूचना संख्या S/21/2026 दिनांक 28.04.2026

क्र.नं.	निविदा संख्या	विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति	मात्रा	T.O.D.
132	07265700	एक वर्ष के लिए रनिंग कोन्ट्रेक्ट:- PVC इंसुलेटेड आर्मर्ड,अनस्क्रीनड, भूमिगत रेलवे सिग्नलिंग केबल, आकार 12 कोर X 1.5 वर्ग मिमी, जो RDSO SPECN संख्या IRS:S-63/2014 (REV 4.0) के अनुरूप हो।	6000 कि.मी.	28-मे-26
133	22263113	सस्पेंशन ट्यूब बेयरिंग का सेट (ड्राइविंग और नॉन-ड्राइविंग)	193 सेट	27-मे-26
134	22262803	रिवर्सर J1 और J2, क्षमता 1500 एम्प्स	27 नंग	25-मे-26
135	11255051	संलग्न विनिर्देशों के अनुसार EOT क्रेन 15/5 टन की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	1 नंग	25-मे-26
136	11245057	25/10 टन EOT क्रेन की आपूर्ति, इरेक्शन और कमीशनिंग	1 नंग	25-मे-26
137	04261706A	लिक्वीफाईड़ पेट्रोलियम गैस	59785 कि.ग्रा.	23-मे-26

शुद्धिपत्र

कृपया टेंडर नोटिस संख्या: S-13-2026, दिनांक: 11.03.2026 के क्रम संख्या 87 पर, अंतिम तिथि को "11.05.2026" पढ़ें।

विस्तृत सूचना, EMD (बयाना राशि), खरीद प्रतिबंधों और विस्तृत टेंडर शर्तों के संबंध में, कृपया वेबसाइट www.ireps.gov.in और wr.indianrailways.gov.in पर जाएं। 0051

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फोलो करें: X.com/WesternRly

पश्चिम रेल्वे

ईलेक्ट्रीकल वर्क

Sr.DEE/P/मुंबई सेंट्रल, मुंबई ई-टेंडर संख्या: EL-166-162-WA-3 (R) दिनांक 29-04-2026 (दो पैकेट प्रणाली) आमंत्रित करता है। कार्य और स्थान: मुंबई मंडल (गैर-उपनगरीय खंड):- पालघर (3), बोईसर (3), दहानू रोड (3), वापी (6) और वलसाड (2) में एस्केलेटर (17 नग) लगाने का प्रावधान (विद्युत और सिविल कार्य के लिए मिश्रित टेंडर)। कार्य की अनुमानित लागत: रु. 30,24,76,871.34/- E M D : रु. 60,49,500/- जमा करने की तिथि और समय: दि.22.05.2026 को 15:00 बजे तक। खोलने की तिथि और समय: दि.22.05.2026 को 15:30 बजे। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं।

0059

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

सूरत इकोनॉमिक रीजन 2047 तक 20 गुना वृद्धि के साथ गुजरात की जीएसडीपी में 35 फीसदी से अधिक का योगदान देगा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 'क्षेत्रीय आकांक्षाएं, वैश्विक महत्वाकांक्षाएं' थीम के साथ वीजीआरसी का भव्य शुभारंभ किया

▸▸ वैश्विक युद्ध, सप्लाई चेन के संकट के बीच भी भारत अडिग : पिछले 4 वर्ष और 60 दिनों से देश में ईंधन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई : केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी

▸▸ मुख्यमंत्री ने दक्षिण गुजरात रीजन के पांच जिलों में 8 नए 'स्मार्ट जीआईडीसी' औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की

▸▸ 'सूरत कट डायमंड' को केंद्र सरकार की ओर से जीआई टैग मिलने के उपलक्ष्य में भारतीय डाक द्वारा जारी विशेष कवर का मुख्यमंत्री ने अनावरण किया

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल

▸▸ सूरत के उद्योगों ने देश की ऐतिहासिक परियोजनाओं में आधारभूत योगदान दिया है

▸▸ दुनिया के सबसे ऊंचे 'चिनाब रेल ब्रिज' और रक्षा क्षेत्र में आधुनिक तोपों के निर्माण में सूरत के उद्योगों का गौरवशाली योगदान

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ गुजरात ने वीजीआरसी का अभिनव दृष्टिकोण अपनाया, ताकि कोई भी क्षेत्र विकास में पीछे न रह जाए, साथ ही जिले की क्षमताओं को वैश्विक प्लेटफॉर्म भी मिले

▸▸ समावेशी विकास की भावना के साथ विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात का निर्माण करने के लिए रीजनल कॉन्फ्रेंस परफेक्ट प्लेटफॉर्म है

▸▸ रीजनल इकोनॉमिक मास्टर प्लान के जरिए विभिन्न क्षेत्रों के सर्वग्राही विकास का लक्ष्य रखा है

▸▸ सूरत इकोनॉमिक रीजन में केमिकल और फार्मा, टेक्सटाइल एंड अपैरल तथा जेम्स एंड ज्वेलरी, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट और टूरिज्म के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं

▸▸ सूरत जल, जमीन और हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट वाला भारत का वेल कनेक्टेड शहर बन रहा है

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▸▸ राज्य सरकार गुजरात में सपने लेकर आए निवेशकों की मित्र, भागीदार और शुभचिंतक है

▸▸ वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के जरिए सूरत सहित दक्षिण गुजरात के विकास को मिलेगी नई ऊर्जा

▸▸ गुजरात देश की कुल जीडीपी में 8.2 फीसदी योगदान के साथ अग्रणी : राज्य की जीडीपी में दक्षिण गुजरात के योगदान को 2047 तक 20 फीसदी तक ले जाने का राज्य सरकार का लक्ष्य

▸▸ औद्योगिक इंसेंटिव के लिए अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सरकार ने बनाई है पारदर्शी व्यवस्था

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को सूरत में तीसरी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) का भव्य शुभारंभ करते हुए साफ कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से गुजरात ने वीजीआरसी का अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि राज्य का कोई भी क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे न रह जाए, साथ ही जिले की क्षमताओं को वैश्विक प्लेटफॉर्म भी मिले।

उन्होंने इससे पूर्व उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ रीजन में आयोजित दो वीजीआरसी की सफलता का संदर्भ देते हुए कहा कि समावेशी विकास की भावना के साथ विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात का निर्माण करने के लिए रीजनल कॉन्फ्रेंस एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है।

उन्होंने आगे कहा कि दक्षिण गुजरात रीजन की वीजीआरसी में सूरत सहित तापी, नवसारी, वलसाड, डांग और भरूच जिले की औद्योगिक विकास की क्षमताओं और संभावनाओं को अधिक वेग मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने सूरत इकोनॉमिक रीजन में केमिकल और फार्मा, टेक्सटाइल एंड अपैरल तथा जेम्स एंड ज्वेलरी, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट और टूरिज्म की निहित संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

उन्होंने यह भी कहा कि, इस अनुमान के साथ कि सूरत इकोनॉमिक रीजन 2047 तक बीस गुना वृद्धि के साथ गुजरात की जीएसडीपी में 35 फीसदी से अधिक का योगदान देगा, नीति आयोग के मार्गदर्शन में सूरत को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने का मास्टर प्लान मंजूर भी हो गया है।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से सूरत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे कॉरिडोर, नेशनल हाईवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, पोर्ट, एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन, मेट्रो रेल और आउटर रिंग रोड आदि से जुड़कर हवाई, जल और जमीनी कनेक्टिविटी के माध्यम से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट वाला भारत का वेल-कनेक्टेड शहर बन रहा है।

मुख्यमंत्री ने गुजरात राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर शुरू हुई दक्षिण गुजरात क्षेत्र की इस वीजीआरसी को प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य में 2001 के बाद हुए आमूल बदलाव और विकास के नए मील के पत्थर का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में बंदरगाह-आधारित विकास सहित हुए निरंतर अप्रतिम विकास का जिक्र करते हुए कहा कि आज गुजरात अकेला देश के कुल कार्गो का 40 फीसदी हैंडलिंग करता है। इतना ही नहीं, गुजरात औद्योगिक उत्पादन (इंडस्ट्रियल आउटपुट) में 18 फीसदी और नवीकरणीय ऊर्जा में 15 फीसदी की हिस्सेदारी रखता है। राज्य सरकार का अपना कर राजस्व 9 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 1.55 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

इसके अलावा, गुजरात ने इन ढाई दशकों में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में बहुत बड़ी छलांग लगाई है। साणंद और धोलेरा सेमीकंडक्टर हब बन गए हैं। अब तक दो सेमीकंडक्टर प्लांट कार्यरत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर्स समिट और प्रधानमंत्री के डेवलपमेंट विजन के परिणामस्वरूप गुजरात आज देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बना गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य का प्रत्येक जिला अपनी विशिष्ट संभावनाओं के साथ आगे बढ़ सके, इसके लिए करीब 20 प्रायोरिटी सेक्टर्स के साथ छह रीजनल इकोनॉमिक मास्टर प्लान तैयार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने विकसित भारत 2047 के लिए विकसित गुजरात 2047 का रोडमैप तैयार किया है। इसमें अर्निंग वेल, लिविंग वेल के ध्येय के साथ 2047 का गुजरात कैसा होगा, इसके लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसकी विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर, ईवी, ग्रीन हाईड्रोजन, और एआई जैसी फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज के जरिए इन्वेस्टमेंट एंड एंप्लॉयमेंट, दोनों को बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने दक्षिण गुजरात की इस वीजीआरसी में सहभागी हो रहे उद्योग-व्यापार जगत के दिग्गजों से विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात बनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने दक्षिण गुजरात रीजन में सूरत जिले में 2, भरूच में 3, वलसाड में 1, तापी में 1 और नवसारी जिले में 1 सहित कुल 5380 एकड़ में आकार लेने वाले 8 नए 'स्मार्ट जीआईडीसी' औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने सभी नागरिकों को गुजरात स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस' के आयोजन से सूरत और दक्षिण गुजरात के विकास को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। वाइब्रेंट गुजरात को क्षेत्रीय स्तर पर ले जाने के लिए अब राज्य के चार जोन में रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही हैं।

श्री संघवी ने वाइब्रेंट गुजरात की दो दशकों की सफलता के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए जोड़ा कि वर्ष 2003 में गुजरात की जीडीपी 1.29 लाख करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर वर्ष 2012-13 में 7.20 लाख करोड़ रुपए हो गई। प्रगति की इस यात्रा को जारी रखते हुए वर्ष 2022-23 में जीडीपी 21.90 लाख करोड़ रुपए और वर्ष 2025 के अंत तक 27.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। गुजरात आज देश की कुल जीडीपी में 8.2 प्रतिशत योगदान के साथ देश का ग्रोथ इंजन बन गया है। उन्होंने इस विकास यात्रा में उद्योगपतियों के अमूल्य योगदान की सराहना की।

राज्य की औद्योगिक क्षमता के बारे में जानकारी देते हुए श्री संघवी ने कहा कि राज्य में एमएसएमई इकाइयों की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) में गुजरात पूरे देश में अग्रणी रहा है। आने वाले समय में बुलेट ट्रेन परियोजना के साकार होने से राज्य में ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा। उद्योगपतियों के लिए नीतिगत सरलता और प्रशासनिक पारदर्शिता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन सहायता (इंसेंटिव) प्राप्त करने के लिए अब उद्योगपतियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में कुल 5,619 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का वितरण किया गया है, जिसके अंतर्गत कल ही सूरत से 11,000 व्यापारियों को 1,300 करोड़ रुपए की सहायता सीधे प्रदान की गई है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गुजरात में सपने लेकर आने वाले निवेशकों की मित्र, भागीदार और शुभचिंतक है। उन्होंने मेहसाणा वीजीआरसी में हुए 3.24 लाख करोड़ रुपए के एमओयू और राजकोट में हुए 5.78 लाख करोड़ रुपए के एमओयू का जिक्र करते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि सूरत में भी रिकॉर्ड संख्या में एमओयू होंगे। प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत @2047' के विजन को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने दक्षिण गुजरात के जिलों को शामिल करते हुए 'सूरत इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान @2047' तैयार किया है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2047 तक राज्य की जीडीपी में दक्षिण गुजरात की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत तक ले जाने की योजना है।

दक्षिण गुजरात की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए श्री संघवी ने कहा कि देश के 60 प्रतिशत सोलर पैनल और सोलर सेल का उत्पादन इस क्षेत्र में हो रहा है। कुशल मानवबल और पोर्ट कनेक्टिविटी के कारण लॉजिस्टिक्स लागत भी बहुत कम आती है। सूरत आज देश के 75 प्रतिशत कपड़े का उत्पादन और निर्यात करता है तथा विश्व के हर 100 में से 90 हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग सूरत में होती है। स्वच्छता में भी सूरत देश में प्रथम स्थान पर होने का गौरव व्यक्त करते हुए उन्होंने उद्योगपतियों से उभरते क्षेत्रों में निवेश करने का आह्वान किया।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्ष 2027 के वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले इस प्रकार की क्षेत्रीय समिट के आयोजन के लिए गुजरात सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की समिट अन्य राज्यों के लिए भी आदर्श और प्रेरणादायक बनी है। वैश्विक स्तर पर बीमा लागत में वृद्धि, कार्गो में देरी और सप्लाई चेन की गंभीर समस्याओं के बीच भी भारत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में सुरक्षित रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वैश्विक युद्ध, आपूर्ति श्रृंखला संकट और हॉर्मुज की खाड़ी में उत्पन्न तनाव के बावजूद केंद्र सरकार ने देशवासियों को आर्थिक बोझ से बचाया है।

इस संदर्भ में श्री पुरी ने कहा कि जब वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल के दामों में भारी वृद्धि हुई है, तब भी पिछले 4 वर्ष और 60 दिनों से देश में पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने पड़ोसी देशों की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश में अप्रैल महीने में पेट्रोल के दामों में 42.7 प्रतिशत और डीजल में 54.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार उत्तर और दक्षिण के पड़ोसी देशों में भी ईंधन के दामों में 39 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि हुई है। विश्व के अन्य बाजारों में लंबी कतारें, राशनिंग और काम के घंटों में कटौती जैसी स्थिति देखने को मिली है, लेकिन भारत ने 'पैनिक' (घबराहट) को कभी अपनी नीति नहीं बनने दिया। भारतीय रसोई में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होने दी गई।

श्री पुरी ने आगे जोड़ा कि कई लोग देश में कीमतों की स्थिरता को चुनाव से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले 4 वर्षों में कई चुनाव आए और गए, फिर भी सरकार की प्रतिबद्धता आम जनता को राहत देने की रही है। सरकार ग्राहकों के हित में कठोर निर्णय लेने में सक्षम है और भविष्य में भी जनहित सर्वोपरि रहेगा।

गुजरात गौरव दिवस के पावन अवसर पर दक्षिण जोन की 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस' की पहली बार मेजबानी करने के लिए सूरतवासियों को बधाई देते हुए केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू हुई 'वाइब्रेंट गुजरात' समिट की सफलता के कारण आज गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं।

सूरत के उद्योगों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री पाटिल ने गौरवपूर्वक कहा कि जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे 'चिनाब रेल ब्रिज' में सूरत की एम/एनएस इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित अत्यंत मजबूत स्टील का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हजीरा स्थित एलएंडटी प्लांट में तैयार की गई आधुनिक तोपें (के9 वज्र) देश की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं। यह केवल सूरत ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात के लिए गौरव का क्षण है।

उन्होंने जोड़ा कि देश में पानी की जरुरतों को पूरा करने के लिए जल संचय के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। जागरूक देशवासियों ने जनभागीदारी से 70 लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया है, जिससे 2 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) अतिरिक्त जल संचय संभव हुआ है। आज 83 प्रतिशत पानी कृषि में उपयोग होता है, जबकि 14 प्रतिशत पानी जनसमुदायों में तथा 2.5 प्रतिशत पानी उद्योगों में उपयोग किया जाता है। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों से भूजल का अनावश्यक दोहन न करने और प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाते हुए जल संरक्षण करने का आह्वान किया।

उन्होंने गर्व के साथ कहा कि महानगर पालिका द्वारा टर्शियरी ट्रीटेड वॉटर बेचकर प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपए से अधिक की आय प्राप्त की जा रही है और सूरत ने आने वाले 50 वर्षों की जल आवश्यकता के लिए ठोस और भविष्योन्मुखी योजना तैयार की है।

उन्होंने आगे कहा कि सूरत के उद्यमी एवं उनकी कार्यक्षमता के कारण ही आज बड़े वैश्विक प्रोजेक्ट्स में सूरत की मजबूत भागीदारी देखने को मिल रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगामी समय में इस रीजनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दक्षिण गुजरात के विकास को नई गति मिलेगी।

भारत स्थित जापान के राजदूत श्री ओनो केइची ने अपने संबोधन की शुरुआत गुजराती भाषा करते हुए कहा, "2009 में जापान पहली बार वाइब्रेंट गुजरात समिट के भागीदार देश के रूप में जुड़ा। तब से हम लगातार गुजरात की पार्टनर कंट्री रहे हैं। उसका हमें बहुत गौरव है।" उन्होंने कहा कि सूरत भारत के अग्रणी व्यापारिक शहरों में एक है तथा डायमंड प्रोसेसिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में बहुत ही विख्यात बना है। जापान-भारत के संबंधों के संदर्भ में हाईस्पीड रेलवे ट्रेन प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण हब के रूप में भी सूरत का बहुत महत्व है।

उन्होंने कहा, "सूरत जैसे महत्वपूर्ण शहर में इस इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन बहुत उल्लेखनीय है। सूरत तथा गुजरात राज्य के अधिक समृद्ध आर्थिक विकास के लिए जापान सदा समर्थन देता रहेगा।"

उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हजीरा में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के स्टील प्लांट में कुल निवेश 1.4 ट्रिलियन रुपए है तथा उसके जरिये लगभग 40 हजार से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। अब तक इस प्लांट द्वारा 7.2 मिलियन टन स्टील का उत्पादन हुआ है और उसे निकट भविष्य में 15 मिलियन टन तक बढ़ाया जाएगा।

सेमीकंडक्टर सेक्टर के बारे में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सरकार तथा निजी कंपनियों के बीच का सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जापान भी भारत में सेमीकंडक्टर का उत्पादन करने के देश के सपने को साकार करने में और विशेषकर गुजरात राज्य में उसका उत्पादन करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट में सूरत एक मेजर हब है तथा जापान सरकार उसका मजबूती से समर्थन कर रही है। निकट भविष्य में इस शहर में आकार ले रहे जापान-इंडिया जॉइंट प्रोजेक्ट के ठोस परिणाम हमें देखने को मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि मारुति-सुजुकी गाय के गोबर से बायोगैस बनाने के एक प्लांट के कंस्ट्रक्शन पर काम कर रही है। यह पहल पर्यावरण पर प्रभाव ही कम नहीं करती है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ाती है और किसानों के लिए आजीविका बढ़ाने में भी योगदान देती है।

उन्होंने कहा, "गत वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जापान यात्रा के कारण दोनों देशों के बीच इस विशेष रणनीतिक वैश्विक भागीदारी ने एक नए युग के स्वर्णिम अध्याय में प्रवेश किया है। आगामी 2027 का वर्ष जापान तथा भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना का 75वां वर्ष है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूत बनाने के लिए मैं 2027 को विशेष वर्ष के रूप में मनाने के लिए भारत की केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा व्यापारी समुदायों के साथ मिलकर केवल दिल्ली में ही नहीं, बल्कि भारत के कई भागों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहता हूं। 75वें वर्ष को वास्तव में अविस्मरणीय तथा विशेष बनाने के लिए मैं गुजरात राज्य के साथ काम करने को आतुर हूं।" उन्होंने गुजरात सरकार का आभार व्यक्त किया।

सिंगापुर के उच्चायुक्त श्री साइमन वोंग ने सभी का 'जय श्री कृष्ण' के साथ अभिवादन करते हुए कहा कि आज का दिन महान है, जब रीजनल कॉन्फ्रेंस के दिन अन्य तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ भी जुड़ी हैं। आज गुजरात का स्थापना दिवस भी है, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और विश्व में लेबर डे भी मनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि गत वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा सिंगापुर के प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक रूप से उच्च स्तर पर गए हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत में सिंगापुर की ओर से सर्वाधिक एफडीआई दर्ज कराया गया है। वर्ष 2014 से अब तक भारत में क्युमुलेटिव एफडीआई 179 बिलियन डॉलर है। जहां तक गुजरात की बात है, तो भारत से सिंगापुर होने वाले निर्यात में 15 प्रतिशत गुजरात से आता है।

उन्होंने कहा कि आज यह कॉन्फ्रेंस सूरत में है। 100 मिलियन डॉलर मूल्य के हीरे सूरत से सिंगापुर एक्सपोर्ट होते हैं। हर चार में से एक डेनिम जींस सूरत से आता है।

उन्होंने कहा, "हम धोलेरा, गिफ्ट सिटी तथा साणंद में सेमीकंडक्टर तथा फाइनेंस क्षेत्र में आगे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने निरंतर सिंगापुर की यात्राएं कीं। इस कारण यह संबंध दीर्घकालीन है। आगामी वाइब्रेंट गुजरात की मुख्य इवेंट में सिंगापुर अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं करेगा।

इस अवसर पर सूरत तथा गुजरात के हीरा उद्योग के लिए गौरव समान 'सूरत कट डायमंड' को केंद्र सरकार की ओर से जीआई टैग मिलने के उपलक्ष्य में भारतीय डाक द्वारा जारी एक विशेष कवर का मुख्यमंत्री ने अनावरण किया गया।

इस मौके पर उपस्थित सभी ने 'वाइब्रेंट गुजरात तथा विकसित गुजरात' की थीम के साथ राज्य के विकास का विजन प्रस्तुत करने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म रुचिपूर्वक देखी।

इस अवसर पर निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव डाइरेक्टर श्री नोबुओ ओकोची, एसोचैम के अध्यक्ष श्री निर्मल मिंडा, रवांडा की उच्चायुक्त श्री जैक्लीन मुकानगीरा, यूक्रेन के उच्चायुक्त ओलेक्सांद्र पोलिशचुक, राज्य सरकार के मंत्री सर्वश्री कनुभाई देसाई, जीतूभाई वाघाणी, ऋषिकेशभाई पटेल, प्रद्युमनभाई वाजा, नरेशभाई पटेल, रमणभाई सोलंकी, डॉ. जयरामभाई गामित, सांसद श्री मुकेशभाई दलाल, विधायक, राज्य के मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, अपर मुख्य सचिव श्री जयंती रवि, उद्योग सचिव श्री ममता वर्मा, निर्वाचित वरिष्ठ पदाधिकारी, सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, दक्षिण गुजरात के डायमंड, टेक्सटाइल आदि क्षेत्र के अग्रणी उद्यमी, युवा उद्यमी, विदेशी उद्योगकार आदि उपस्थित रहे।

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के पहले दिन सूरत में 'नारी शक्ति वंदन' सेमिनार आयोजित

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राष्ट्र निर्माण के स्तंभ के रूप में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया, सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की

▸▸ महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास सशक्त परिवार और विकसित भारत की ओर : डॉ. जयंती रवि, अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग

गांधीनगर : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के पहले दिन शुक्रवार को सूरत में 'शक्ति संगम : गुजरात विकसित भारत के विकास इंजन के रूप में' विषयवस्तु पर 'नारी शक्ति वंदन' सेमिनार आयोजित हुआ।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ममता वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार तथा रवांडा की भारत स्थित उच्चायुक्त सुश्री जैकलिन मुकांगिरा मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को शक्ति का स्रोत माना जाता है और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं को समान अवसर देने और उनके सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्थानीय निकायों में 50 फीसदी आरक्षण प्रदान किया गया है, जबकि विधानसभाओं और लोकसभा में 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे नेतृत्व, निर्णय-प्रक्रिया और राष्ट्र-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बना रही हैं।

राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि ने कहा कि देश महिलाओं के विकास से हटकर अब 'महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास' की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की मुख्य प्रेरक शक्ति बन रही हैं।

उन्होंने कन्या केळवणी अभियान के सफल कार्यान्वयन से शिक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों का उल्लेख किया और महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की जरूरत पर बल दिया।

दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला विंग की अध्यक्ष सुश्री अंकिता वालंदे ने कहा कि यह वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस गुजरात को वैश्विक औद्योगिक शक्ति के रूप में मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। उन्होंने टेक्सटाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मास्युटिकल्स और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के योगदान को रेखांकित किया।

सेमिनार के दौरान 'शक्ति संगम' विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में सुरक्षा, समाज सेवा, उद्यमशीलता और शासन में महिलाओं की भूमिका पर व्यापक मंथन किया गया। दूसरी पैनल चर्चा में 'सूरत में नारी शक्ति : विकसित सूरत से विकसित भारत' विषय के अंतर्गत एआई, डिजिटल इकोसिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान पर प्रकाश डाला गया।

इन स्तंभों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से महिलाएं केवल अपनी स्वयं की प्रगति ही सुनिश्चित नहीं कर रही हैं, बल्कि सुदृढ़ परिवारों, सशक्त समाजों तथा प्रगतिशील एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र को प्रोत्साहन देकर 'विकसित भारत@2047' के विजन को भी गति दे रही हैं।

पैनल में गुजरात कैडर की आईपीएस सूरत साइबर क्राइम की उपायुक्त श्रीमती बिशाखा जैन, गेट्स फाउंडेश की इंडिया कंट्री डायरेक्टर सुश्री अर्चना व्यास, उपासना की संस्थापक सुश्री उमा प्रजापति, 'सखी' एवं ऑरोविल की संस्थापक एवं सीईओ सुश्री देवी नमसिवयम, साधना फॉरेस्ट की सह-संस्थापक सुश्री योरित रोजिन और एसोचैम की हेड-स्टेट्स (ऑल इंडिया) सुश्री परमिंदर जीत कौर सहित अनेक महानुभाव उपस्थित रहे।

सत्र में प्रधानमंत्री के 5एफ फॉर्मूला का उल्लेख किया गया, जो फार्म (खेत) से लेकर फाइबर, फैक्ट्री, फैशन से फॉरेन (विदेश) तक कपड़े की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने का एक व्यापक विजन प्रस्तुत करता है। सत्र में महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, डिजिटल सशक्तिकरण और कौशल विकास को समावेशी शहरी विकास की प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में रेखांकित किया गया, जिसमें महिलाओं को सृजनकर्ता, नेता और निर्णयकर्ता के रूप में विशेष महत्व दिया गया। इसमें यह भी बताया गया कि किस प्रकार एआई और डिजिटल इकोसिस्टम में महिलाओं की भागीदारी परिवारों को मजबूत कर रही है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है और सूरत को विकसित भारत की ओर अग्रसर कर रही है।

इस अवसर पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अनावरण किया गया। इसके अलावा, उद्योग एवं खान विभाग और जिनाश गारमेंट के बीच 6 करोड़ रुपए के निवेश के साथ महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत सूरत और नवसारी जिले में लगभग 1000 महिलाओं को रेडीमेड गारमेंट क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों की औसत मासिक आय लगभग 11,000 होने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन करने वाली महिला उद्यमियों को सम्मानित किया। पूरे सेमिनार ने महिला सशक्तिकरण को विकास के केंद्र में रखने की दिशा में मजबूत संदेश दिया।

रायन इंटरनेशनल स्कूल, चेंबूर ने फ़िर से रचे शैक्षणिक उत्कृष्टता के नये प्रतिमान

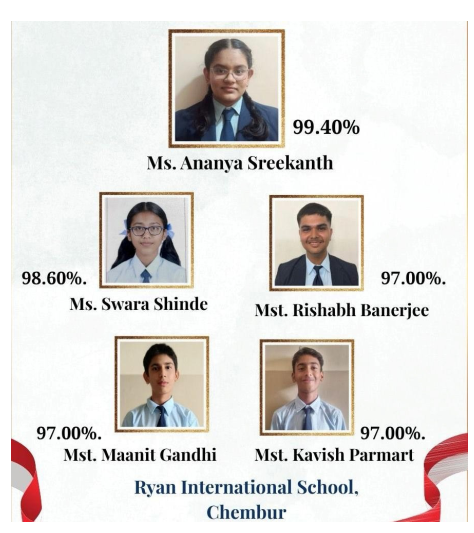

मुंबई। मुंबई के प्रमुख शिक्षा संस्थान रायन इंटरनेशनल स्कूल, चेंबूर ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए आईसीएसई परीक्षा में अपने विद्यार्थियों की असाधारण उपलब्धियों की बदौलत शैक्षणिक उत्कृष्टता के नये प्रतिमान रचते हुए एक बार फ़िर से शानदार सफलता का परचम लहराया है।

यह जानकारी देते हुए रायन इंटरनेशनल स्कूल की वरिष्ठ शिक्षिका तथा मुंबई की सुपरिचित साहित्यकार श्रीमती प्रमिला शर्मा ने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 की दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में रायन इंटर नेशनल स्कूल, चेम्बूर का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा है। परिणाम घोषित होने पर विद्यालय में समारोहपूर्वक ख़ुशियाँ मनाईं गईं। उन्होंने बताया कि रायन इंटरनेशनल स्कूल, चेंबूर ने हाल ही में हुई परीक्षाओं में 100% रिज़ल्ट पाकर गर्व महसूस किया है, जो एकेडमिक एक्सीलेंस के उसके सफ़र में एक और मील का पत्थर है। उन्होंने बताया कि यह शानदार उपलब्धि स्कूल के होलिस्टिक एजुकेशन, डिसिप्लिन्ड लर्निंग और लगातार एकेडमिक सपोर्ट के लिए पक्के कमिटमेंट को दिखाती है। मेधावी और सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों के इस ग्रुप को लीड करते हुए अनन्या श्रीकांत ने शानदार 99.40% हासिल किये। उसके बाद स्वरा प्रशांत शिंदे ने 98.60% अंक प्राप्त किये। उन्होंने कहा कि स्कूल को ऋषभ बनर्जी, कविश अमित परमार और मानित हेमल गांधी के शानदार परफॉर्मेंस पर भी बहुत गर्व है, जिन्होंने 97 % अंक स्कोर करके खुद को टॉप अचीवर्स में शामिल किया है। यह ओवर ऑल रिज़ल्ट एनालिसिस स्कूल के मज़बूत एकेडमिक परफॉर्मेंस को बखूबी दिखाता है। उन्होंने बताया कि कुल 14 स्टूडेंट्स ने 95% से ज़्यादा स्कोर किया, जबकि 64 स्टूडेंट्स ने 85% और 94% के बीच स्कोर किया। इसके अलावा, 48 स्टूडेंट्स ने 75% से 84% तक मार्क्स हासिल किए, और 15 स्टूडेंट्स ने 60% से 74% के बीच स्कोर किया। खास बात यह है कि किसी भी स्टूडेंट ने 60% से कम स्कोर नहीं किया, जो इंस्टीट्यूशन के लगातार बेहतरीन एकेडमिक स्टैंडर्ड को दर्शाता है। एग्जाम देने वाले कुल स्टूडेंट्स की संख्या 141 थी। उन्होंने कहा कि यह शानदार कामयाबी स्टूडेंट्स की लगन और कड़ी मेहनत का पुख़्ता सबूत है। साथ ही यह स्कूल की बहुत ही समर्पित फैकल्टी की लगातार कोशिशों को भी दिखाता है, जिनके गाइडेंस और मेंटरशिप ने इन सफलताओं को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। उनका मानना है कि माता- पिता से लगातार हिम्मत और सपोर्ट ने इस कामयाबी को और मज़बूत किया है। उन्होंने कहा कि हमारे छात्र-छात्राओं की सफलता हमारी सम्माननीय प्रबंधन टीम के अथक प्रयासों और समर्पण का भी प्रमाण है। विद्यार्थियों की प्रतिभा को पोषित करने में दूरदर्शी नेतृत्व और अटूट समर्थन के लिए अध्यक्ष डॉ. ए. एफ. पिंटो और प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो का योगदान अतुलनीय रहा है। विद्यालय के चेयरमैन ने सभी विद्यार्थियों को बधाइयाँ देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ प्रकट की हैं। उन्होंने कहा कि चेंबूर के रायन इंटरनेशनल स्कूल में, हम युवा दिमागों को न केवल एकेडमिक रूप से बल्कि कैरेक्टर और वैल्यूज़ में भी बेहतरीन बनाने में यकीन रखते हैं।

महंगी गैस से सूरत का टेक्सटाइल उद्योग संकट में : उत्पादन घटा, कीमतों में बढ़ोतरी के आसार

सूरत के देशभर में प्रसिद्ध टेक्सटाइल हब पर इस समय एक नया आर्थिक दबाव गहराता जा रहा है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में हाल ही में हुई करीब 993 रुपये की तेज बढ़ोतरी ने उद्योग की रीढ़ माने जाने वाले डाइंग, प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग सेक्टर को झकझोर कर रख दिया है। पहले से ही वैश्विक ऊर्जा महंगाई, कमजोर मांग और बढ़ती प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे इस उद्योग के सामने अब लागत का नया संकट खड़ा हो गया है। टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े व्यापारी गिरधर गोपाल मूंदड़ा के अनुसार, इस बढ़ोतरी का सबसे सीधा और गंभीर असर उन यूनिट्स पर पड़ा है जो ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भर हैं। डाइंग और प्रोसेसिंग जैसे कार्यों में बड़ी मात्रा में गैस की जरूरत होती है, और LPG की कीमत बढ़ने से प्रति मीटर और प्रति किलो प्रोसेसिंग लागत में उल्लेखनीय इजाफा हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कई छोटे और मध्यम स्तर के यूनिट्स ने अपने उत्पादन में कटौती कर दी है, जबकि कुछ इकाइयों ने अस्थायी रूप से काम बंद करने का फैसला भी लिया है। यह संकट केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर श्रम बाजार पर भी साफ नजर आने लगा है। बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत में इजाफे के कारण मजदूरों का पलायन बढ़ रहा है। सूरत जैसे शहर में, जहां टेक्सटाइल उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है, वहां श्रमिकों की कमी उत्पादन क्षमता को सीधे प्रभावित कर रही है। कई यूनिट्स को पर्याप्त कामगार नहीं मिल पा रहे, जिससे मशीनें होने के बावजूद उत्पादन पूरी क्षमता से नहीं हो पा रहा है। सूरत का सिंथेटिक टेक्सटाइल सेक्टर, जिसे MMF (मैन-मेड फाइबर) के नाम से जाना जाता है, इस समय दोहरे दबाव में है। एक ओर कच्चा माल, जो कि क्रूड ऑयल पर आधारित होता है, पहले ही महंगा हो चुका है, वहीं दूसरी ओर LPG की बढ़ी कीमतों ने प्रोसेसिंग लागत को और अधिक बढ़ा दिया है। इसके मुकाबले कॉटन सेक्टर पर असर अपेक्षाकृत कम जरूर है, लेकिन वह भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। डाइंग, ट्रांसपोर्ट और अन्य प्रोसेसिंग लागत बढ़ने के कारण वहां भी लागत का दबाव महसूस किया जा रहा है। उद्योग से जुड़े जानकारों का कहना है कि इस लागत वृद्धि का सीधा असर आने वाले समय में उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। यार्न और प्रोसेसिंग दोनों की लागत बढ़ने से कपड़ों की कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। हालांकि फिलहाल उद्योग इस बढ़े हुए बोझ को ग्राहकों पर तुरंत नहीं डाल पा रहा है, क्योंकि बाजार में मांग कमजोर है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी टेक्सटाइल सेक्टर सुस्ती का सामना कर रहा है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी इतनी अधिक है कि कीमत बढ़ाना आसान नहीं है।